



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 229]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्वाय अथवा नॉन-एल्वाय स्टील के वॉयर रॉड" के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने संबंधी जांच।

एफ. सं. 14/17/2016—डीजीएडी.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मेसर्स स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, मेसर्स ऊषा मार्टिन लिमिटेड और मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड (जिन्हें आगे "याचिकादता कंपनियां" अथवा "आवेदक" कहा गया है) ने अधिनियम और पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्वाय अथवा नॉन-एल्वाय स्टील के वॉयर रॉड" (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरुआत करने के साथ-साथ संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के लिए जांच शुरू करने का भी अनुरोध किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरू करने के लिए दिनांक 02 जून, 2016 की अधिसूचना जारी की थी, जो कि भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई थी, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

3. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में दिनांक 27.09.2016 को अधिसूचना संख्या 14/17/2016-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम द्वारा अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने सीमा-शुल्क की एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके द्वारा प्राधिकारी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सीमा-शुल्क की दिनांक 02.11.2016 की अधिसूचना संख्या 51/2016-सीमा-शुल्क द्वारा अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया था।

क. क्रिया-विधि

4. इस जांच में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (क) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्रवाई करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया है।
- (ख) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पतों के अनुसार संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, और भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत करा दें।
- (ग) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रति प्रेषित की थी। आवेदन-पत्र की एक प्रति ऐसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी, जिन्होंने उसके लिए अनुरोध किया था।
- (घ) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।
- (ङ) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-
 1. जिउक्वान ऑयरन एंड स्टील (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड
 2. हंडन ऑयरन एंड स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 3. लियानयुआन ऑयरन एंड स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 4. बाओस्टील ग्रुप कार्पोरेशन
 5. बुहान ऑयरन एंड स्टील (ग्रुप) कार्पोरेशन
 6. बेनेक्सी ऑयरन एंड स्टील (ग्रुप) स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड
 7. लिंगुआन ऑयरन एंड स्टील (ग्रुप) कंपनी लिमिटेड
 8. शोऊगांग चांगझी ऑयरन एंड स्टील लिमिटेड
 9. हांगझाऊ ऑयरन एंड स्टील ग्रुप कंपनी
 10. एनफेंग स्टील स्ट्रक्चर मेटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
 11. टिआन्जिन क्सुयुआन ऑयरन एंड स्टील ट्रेडिंग कंपनी
- (च) जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों/व्यापारियों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-
 1. जिआंग्सू शागांग मेटेरियल ट्रेड कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)
 2. बी एंड आई मेटल (एचके) लिमिटेड (निर्यातक)
 3. जिआंग्सू रूनझोंग हाई टेक कंपनी कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)

4. झांगजिगांग शाजिंग स्टील कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
5. झांगजिगांग होंगक्सिंग गाओक्सिआन कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
6. झांगजिगांग रोंगशेंग स्टील मेकिंग कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
7. जिआंगसू शागांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)
8. बी एंड आई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)
9. झांगजिगांग होंगचांग गाओक्सिआन कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
10. झांगजिगांग रून्झोंग स्टील कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
11. किसनशा इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड (निर्यातक)
12. मिनमेटल्स जिंगक्यू मीडियम प्लेट कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
13. सिनोमेटेरियल इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)
14. मनुचर स्टील हांग कांग लिमिटेड (निर्यातक)
15. बुरविल रिसोर्सिज लिमिटेड (निर्यातक)
16. जिआंगसू योनगांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
17. जेनेसिस रिसोर्सिज कंपनी लिमिटेड (हांग कांग)
18. स्मार्ट टाईमिंग स्टील लिमिटेड (निर्यातक)
19. टोपटिप होल्लिंग प्राईवेट लिमिटेड (निर्यातक)
20. जेनिथ स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
21. हांगझाऊ कोजेनरेशन (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)
22. यूनीस्टील इंटरनेशनल डीएमसीसी (निर्यातक)
23. विन फेथ ट्रेडिंग लिमिटेड (निर्यातक)
24. बेनेक्सी ऑयरन एंड स्टील हांग कांग लिमिटेड (निर्यातक)
25. बेनेक्सी बेईजिंग ऑयरन एंड स्टील ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (निर्यातक)
26. बेनेक्सी बेईटाई गाऊसू स्टील वायर रॉड कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
27. फ्यूचर मेटेरियल्स इंडस्ट्री (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)
28. जिआन्गिन किंसंगचेंग एलवाय मेटेरियल कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)
29. जिआन्गिन किंसंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लिमिटेड (निर्यातक)

(छ) इनके अतिरिक्त निम्नलिखित निर्यातकों/व्यापारियों ने प्रश्नावली के पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करने के बजाय केवल परिशिष्ट-2 और 3-क प्रस्तुत किए हैं:-

1. हांग कांग ग्रांड इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
2. ह्योसूंग कार्पोरेशन
3. स्टीलको पेसिफिक ट्रेडिंग लिमिटेड
4. स्टीलफोर्स फार ईस्ट लिमिटेड
5. टाटा इंटरनेशनल मेटल्स (एशिया) लिमिटेड
6. यूनीस्टील इंटरनेशनल डीएमसीसी (पृथक रूप से प्रस्तुत किया है)

- (ज) चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का खंडन करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) का दावा नहीं किया है।
- (झ) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:-

1. ए.ए. इंटरनेशनल
2. अग्रवाल इंप्स
3. डी. पी. वायरस प्राईवेट लिमिटेड
4. गर्ग इनोक्स लिमिटेड
5. एच. डी. वायरस प्राईवेट लिमिटेड
6. इंडियन वायर एंड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
7. जे. एस. इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
8. कादिमी स्पेशल स्टहल्स प्राईवेट लिमिटेड
9. लक्ष्मी कार्ड क्लोदिंग मेन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
10. मकालू ट्रेडिंग लिमिटेड
11. निर्मल वायरस प्राईवेट लिमिटेड
12. ओसेनिक ऑवरसीज
13. पंकज स्टील कार्पोरेशन
14. आर. के. स्टील्स
15. स्टरलिंग टूल्स लिमिटेड
16. ट्रांसनेशनल
17. उदय इंडस्ट्रीज
18. वी. एन. सी. इलेक्ट्रोड्स
19. विधि इम्पेक्स
20. वेल्डवेल इलेक्ट्रोड्स
21. जतिन स्टील्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
22. जरहक स्टील लिमिटेड

- (ट) संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्धारित प्रपत्र में प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

1. अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2. राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड
3. नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनईआईएल)
4. इंडियन वायर एंड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
5. एफएजी बीयरिंग इंडिया लिमिटेड

- (ठ) जांच की कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों ने निवेदन किए हैं/टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं:-

1. चाईना चेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोमर्स ("सीसीओआईसी")
2. जिआंगसू योंगगांग ग्रुप कंपनी लिमिटेड

3. साईनोमेटेरियल इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
4. मनुचर स्टील हांग कांग कंपनी लिमिटेड
5. बुरविल रिसोर्सिज लिमिटेड
6. जेनिथ स्टील ग्रुप कंपनी लिमिटेड
7. स्मार्ट टाईमिंग स्टील लिमिटेड
8. टोपटिप होलिंग प्राईवेट लिमिटेड
9. मिनमेटल्स जिंगकोऊ मीडियम प्लेट कंपनी लिमिटेड
10. बेंक्सी बेईटाई गाऊसू स्टील वायर रोड कंपनी लिमिटेड
11. बेंक्सी बेईयिंग ऑयरन एंड स्टील ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
12. बेंक्सी ऑयरन एंड स्टील हांग कांग कंपनी लिमिटेड
13. फ्यूचर मेटेरियल्स इंडस्ट्री (हांग कांग)
14. हांगझाऊ कोजेनरेशन (हांग कांग) कंपनी लिमिटेड
15. यूनीस्टील इंटरनेशनल डीएमसीसी
16. विन फेथ ट्रेडिंग कंपनी
17. निंगबो सीआईएमईआई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
18. नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनईआईएल)
19. बॉल एंड रोलर बीयरिंग मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
20. स्टील वायर मेन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसडब्ल्यूएमएआई)
21. जिआईगिन किसनचेंग एल्यूवाय मेटेरियल कंपनी लिमिटेड एंड जिआईगिन किसनचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लिमिटेड
22. एफएजी बीयरिंग इंडिया लिमिटेड
23. जिआंगसू शांगांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड

- (ड) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुला रख कर उपलब्ध कराया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को वर्तमान प्रकटन विवरण में शामिल किया गया है।
- (ढ) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी दायर करें।
- (ण) जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मंगाई गई थी।
- (त) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।
- (थ) क्षति रिहत कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई

सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत, निर्माण और बेचने की लागत के आधार पर है निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

- (द) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध वस्तुओं को विभिन्न ग्रेडों/आकारों/परिमाण में आयात किया जा रहा है, आवेदकों ने उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है, ताकि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए पीसीएन से पीसीएन की तुलना की जा सके। तथापि, मामले के वास्तविक सांचे को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने पीसीएन से पीसीएन की तुलना करने की प्रणाली को नहीं अपनाया है।
- (ध) प्राधिकारी द्वारा जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन किया गया है। जहां कहीं भी लागू होता है, वहां केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर ही उसमें आवश्यक संशोधन सहित विश्वास किया गया है।
- (न) यह जांच 1 जुलाई, 2015 से ले कर 31 दिसंबर, 2015 (6 मास) तक की गई थी (जिसे आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है)। क्षति का विश्लेषण करने के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 तथा जांच अवधि को भी शामिल किया गया है।
- (प) याचिकादाताओं ने यह याचिका प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने आईबीआईएस स्रोत से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़ों पर विश्वास करके संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने का आरोप लगाया है। तथापि, वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारोबार-वार आंकड़े प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आयातों के कारोबार-वार आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (फ) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करने के लिए 04 मई, 2017 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई में उपस्थित सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में 09 मई, 2017 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें और साथ ही उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रत्युत्तर 15 मई, 2017 तक प्रस्तुत कर दें।
- (ब) जांच की कार्यवाही के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों को और प्रदान की गई सूचना को उसके साक्ष्य सहित और वर्तमान जांच में जितना प्रासंगिक पाया गया है, प्राधिकारी द्वारा उस पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- (भ) सीमा-शुल्क के आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के लिए विचारित अमरीकी डालर को भारतीय रूपयों में परिवर्तन करने के लिए विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 65.93 रूपए है।
- (म) इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।
- (य) 12.08.2017 को हितबद्ध पक्षकारों को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था, जिसमें इस जांच के अनिवार्य तथ्य शामिल थे, जोकि इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनते हैं। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पश्चात अनुरोधों पर विचार किया गया है, जो इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना में हृद तक सुसंगत पाए गए हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:-

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ऑयरन अथवा नॉन-एल्वॉय स्टील अथवा एल्वॉय स्टील के अनियमित रूप से वाउंड क्वार्टर्स बार्स और रॉड्स और हॉट रोलड है (जिन्हें सामान्यतया वायर रॉड्स के रूप में जाना जाता है)।

ये उत्पाद मुख्य और गैर-मुख्य श्रेणी के हैं और सभी आकारों के हैं। ये उत्पाद स्टील्स की विभिन्न गुणधर्मताओं को पूरे करते हैं, जिनमें सभी निहित होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोड तक सीमित होते हैं, फ्री कटिंग, डलाई, कॉल्ड हैडिंग, कम/मध्यम/अधिक कार्बन स्टील्स, ड्राईंग, बाल बीयरिंग स्टील, केस हार्डनिंग, स्प्रिंग स्टील, जंग-रोधी स्टील, विदरिंग स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील और अनेक अन्य कोटि की स्टील तक ही सीमित नहीं है। तथापि, निम्नोक्त उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जाता है।

(क) इंडेंटेशन सहित बार्स और रॉड्स, रिब्स, गून्स अथवा अन्य डिफॉर्मेशन जो कि रोलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पादित होते हैं, जो कि टैरिफ मद 721310990 के अंतर्गत आते हैं (जिन्हें सामान्यतया रिबार्स अथवा टीएमटी बार्स के नाम से जाना जाता है)।

(ख) टैरिफ शीर्ष 7221 के अंतर्गत आने वाले बार्स और रॉड्स।

(ग) टैरिफ शीर्ष 72271000 के अंतर्गत आने वाले तीव्र गति के स्टील के बार्स और रॉड्स।

6. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग अनेक अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव संघटक, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फास्टनर्स जिनमें नट और बोल्ट्स, कीलें, रेलवे स्लीपर्स, सामान्य अभियांत्रिकी, निमार्ण उद्योग के लिए बाईंडिंग वायर्स, आर्मर्ड केबिल्स आदि शामिल हैं।

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ शीर्ष 7213 और 7227 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

ख 1. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों पर निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) आवेदकों द्वारा कोई "समान वस्तु" उत्पादित नहीं की जा रही है। घरेलू उद्योग उच्च कोटि के बीयरिंग्स का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित कुछ गुणवत्ता प्राचलों को पूरा करने में असमर्थ है। हालांकि घरेलू स्टील उत्पादक ऑक्सीजन स्तर > 10 पीपीएम से स्टील का उत्पादन करने में सक्षम है, लेकिन वे ऐसे आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं जिनमें इस तरह से बना कर रखा गया ऑक्सीजन का स्तर 6-8 पीपीएम से कम होता है।

(ख) वायर रॉड्स के निम्नोक्त कुछ हाई एंड ग्रेडों को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

(1) एसआई 52100 ग्रेडों के वायर रॉड्स - जिनका उपयोग बीयरिंग नीडल वायर निर्मित करने के लिए किया जाता है।

(2) ऑटोमोबाइल्स उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले क्रिटिकल स्प्रिंग वायर्स निर्मित करने के लिए हाई एंड स्प्रिंग वायर रॉड्स।

(3) ऑटोमोबाइल्स उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले टायर रॉड्स निर्मित करने के लिए हाई एंड टायर कार्ड वायर रॉड्स।

(4) स्प्रिंग स्टील वायर, पीसी वायर एसीएसआर कोर वायर आदि जैसी वायर्स निर्मित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उच्चतर कार्बन सीमा (0.85 और उससे अधिक) के वायर रॉड्स।

(ग) उच्च कार्बन ग्रेड के स्टील को उत्पाद के दायरे से इस कारण से बाहर रखा जाना चाहिए कि इसकी मांग-पूर्ति में अंतर व्याप्त है।

(घ) भारत में बीयरिंग ग्रेड वायर/वायर रॉड्स का मेसर्ज मुकुन्द लिमिटेड नामक केवल एक ही विनिर्माता है। यहां तक कि मेसर्ज मुकुन्द लिमिटेड उत्पाद की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त मेसर्ज मुकुन्द लिमिटेड पाटन-रोधी शुल्क को लागू करने का अनुरोध करने वाला हितबद्ध पक्षकार भी नहीं है। एचएस संहिताओं 72283019, 72283029, 72299000, 72279030, 72279040 और 72279090 को जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। "बीयरिंग ग्रेड" को संबद्ध जांच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए और भारतीय एचएस वर्गीकरण 7227, 72279030,

72279040 और 72279090 के अंतर्गत आने वाले "बीयरिंग ग्रेड बार्स और वायर रॉड्स" के आयातों पर शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए।

- (ड) टैरिफ मद 72279040 और 72279090 के अंतर्गत आने वाले "एसआई 52100 और एसआई 8720 ग्रेड के वायर रॉड्स" को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग एसआई 52100 और एसआई 8720 के विनिर्देशनों युक्त समान वस्तुओं का विनिर्माण नहीं कर रहा है।
- (च) इसके अतिरिक्त एनईआईएल ने यह आरोप लगाया है कि स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया ("सेल") एसआई 52100 ग्रेड के विशेष आर्डर देने में विफल रहा है और उसने प्रदानगी की विफलता के गोपनीय साक्ष्य के साथ-साथ एनईआईएल और सेल के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के कार्यवृत्त प्रस्तुत किए हैं।
- (छ) घरेलू उद्योग भारतीय एचएस वर्गीकरण 7227, 72279030, 72279040 और 72279090 के अंतर्गत आने वाले "बीयरिंग ग्रेड बार्स और वायर रॉड्स" के उत्पादन को प्रमाणित करने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।
- (ज) यह निवेदन किया जाता है कि टैरिफ शीर्ष 7213/7214 के वायर रॉड्स और टैरिफ शीर्ष 7227/7228 के बार्स की विनिर्माण प्रक्रियाएं भिन्न हैं और इनके लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 7214 और 7228 समान वस्तुएं नहीं हैं और इसलिए ये इस जांच की विषय वस्तु से बाहर हैं।
- (झ) परिभाषित किया गया विचाराधीन उत्पाद अत्यंत अस्पष्ट, व्यापक और अव्यवस्थित है। इसमें सभी प्रकार की वायर रॉड्स निहित हैं, जिनमें ऐसी भी वायर रॉड्स भी शामिल हैं, जिनका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है। उत्पाद की विवरणिका के अनुसार जेएसडब्ल्यू 22 एमएम व्यास तक के आकार की बीयरिंग स्टील से भिन्न वायर रॉड्स का निर्माण करने में सक्षम है। आरआईएनएल 144 एमएम व्यास से अधिक आकार के वायर रॉड्स का निर्माण करने में सक्षम नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 14 एमएम व्यास के आकार तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और इसमें सभी आकारों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- (ञ) 100 के 6 ग्रेड के एलवाय स्टील बार्स, जो कि सेल के 52100 ग्रेड के समान हैं, उनका उत्पादन आवेदकों द्वारा नहीं किया जाता है और इन्हें उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है।

ख 2. घरेलू उद्योग के विचार

9. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) घरेलू उद्योग के पास ऑटोमोबाईल में प्रयुक्त होने वाले और एसआई 52100 के समकक्ष ग्रेडों के हाई एंड स्प्रिंग वायर स्टील वायर रॉड्स, हाई एंड कोर्ड वायर रॉड्स निर्मित करने की क्षमता है और वह इनका निर्माण कर रहा है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा अनुचित है कि इन ग्रेडों को बाहर रखा जाए।
- (ख) एनईआईएल के इस आरोप के संबंध में कि स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया ("सेल") एसआई 52100 ग्रेड के विशेष आर्डर देने में विफल रहा है, घरेलू उद्योग का निवेदन है कि एनईआईएल साक्ष्य का अगोपनीय वृत्तान्त प्रस्तुत करने में विफल रहा है। साक्ष्य का अगोपनीय वृत्तान्त उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में घरेलू उद्योग उस पर अपनी टिप्पणियां देने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त एनईआईएल के आरोपों को स्वीकार किए बिना घरेलू उद्योग का निवेदन है कि घरेलू उद्योग के एक संघटक द्वारा गैर-प्रदानगी की एक स्वतंत्र घटना एक विशेष ग्रेड को उत्पाद के दायरे से बाहर रखे जाने का आधार नहीं हो सकती है।
- (ग) "हाई कार्बन ग्रेड स्टील" के लिए मांग-पूर्ति में व्याप्त अंतर, उसे उत्पाद के दायरे से बाहर रखे जाने का आधार नहीं हो सकता है। तथ्य यह है कि एक विशेष उत्पाद का भारत में पाटन किया जा रहा है और उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और यही शुल्कों को लागू किए जाने का आधार है। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों को हाई कार्बन वायर रॉड की किस्म का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए जिसे वे उत्पाद के दायरे बाहर रखे जाने की मांग कर रहे हैं। विशिष्ट ग्रेड के उपलब्ध नहीं होने से इस मुद्दे का खंडन करने के लिए विस्तार से कोई निवेदन नहीं किया जा सकता है।
- (घ) घरेलू उद्योग के पास टैरिफ मद 7227 9030 के अंतर्गत आने वाली वायर बीयरिंग कोटि के वायर रॉड्स

और टैरिफ मद 7227 9040 के अंतर्गत आने वाली कोल्ड हैडिंग कोटि की वायर रॉड्स निर्मित करने की क्षमता है और वह इनका निर्माण कर रहा है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा अनुचित है कि इन ग्रेडों को बाहर रखा जाए।

- (ड) वर्तमान आवेदन-पत्र सीमा-शुल्क टैरिफ के टैरिफ शीर्ष 7213 और 7227 के अंतर्गत आने वाली क्वायल फार्म में रॉड्स से संबंधित है। वर्तमान आवेदन-पत्र में टैरिफ शीर्ष 7214 और 7228 के अंतर्गत आने वाले सीधी लम्बाई की बार्स और रॉड्स शामिल नहीं हैं। इसलिए टैरिफ शीर्ष 7214 और 7228 के अंतर्गत आने वाले बार्स और रॉड्स को बाहर रखे जाने के हितबद्ध पक्षकारों के दावे का कोई औचित्य नहीं है।
- (च) टैरिफ शीर्ष 7227 9090 के अंतर्गत आने वाली वायर रॉड्स को बाहर रखे जाने के हितबद्ध पक्षकारों के दावे पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि हितबद्ध पक्षकार स्पष्ट रूप से यह विनिश्चित नहीं कर दें कि किस ग्रेड को बाहर रखे जाने की आवश्यकता है। टैरिफ मद 7227 9090 अवशिष्ट शीर्ष ("अन्य") है और इसके कार्य-क्षेत्र में व्यापक श्रृंखला के उत्पादों को शामिल किया जाता है।
- (छ) टैरिफ मद 7229 9090 के अंतर्गत आने उत्पादों को बाहर रखे जाने के हितबद्ध पक्षकारों के दावे का इसलिए कोई औचित्य नहीं है क्योंकि टैरिफ शीर्ष 7229 "अन्य एल्वाय स्टील की वायर" से संबंधित है। वर्तमान आवेदन-पत्र वायर रॉड्स से संबंधित है और न कि वायर से।
- (ज) हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 14 एमएम के व्यास तक सीमित रखा जाए क्योंकि घरेलू उद्योग को जब कभी भी आर्डर दिया जाता है, तो घरेलू उद्योग के पास 14 एमएम से अधिक व्यास की संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने की क्षमता विद्यमान होती है। वास्तव में हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि उन्हें 14 एमएम से अधिक व्यास के विचाराधीन उत्पाद की आवश्यकता है और उन्होंने घरेलू उद्योग को अधिक व्यास के उत्पादों के आर्डर दिए थे, लेकिन घरेलू उद्योग उसकी आपूर्ति करने में विफल रहा है। हितबद्ध पक्षकारों से ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होने पर विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 14 एमएम के व्यास तक सीमित रखने का कोई आधार नहीं है।
- (झ) घरेलू उद्योग के पास 6-8 पीपीएम स्तर से कम ऑक्सीजन युक्त रॉड्स का निर्माण करने की क्षमता है और वह इनका निर्माण कर रहा है।
- (ञ) घरेलू उद्योग के पास 100 के 6 ग्रेड के एल्वाय स्टील के रॉड्स का निर्माण करने की क्षमता है और वह इनका निर्माण कर रहा है।

ख 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों पर हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निदान किया गया है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

11. कुछ उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखे जाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के संबंध में प्राधिकारी निम्नोक्त कारणों से हितबद्ध पक्षकारों के ऐसे दावों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रयुक्त होने वाले हाई एंड स्प्रिंग वायर रॉड्स, हाई एंड टायर कोर्ड वायर रॉड्स, उच्च कार्बन श्रृंखला (0.85 और उससे अधिक) वायर रॉड्स का निर्माण कर रहा है, जिनका उपयोग स्प्रिंग स्टील वायर, पीसी वायर, एसीएसआर कोर वायर आदि जैसी वायर्स का निर्माण करने के लिए किया जाता है और साथ ही यह एसआई 52100 और एसआई 8720 तक के समकक्ष ग्रेड भी निर्मित कर रहा है।
- (2) घरेलू उद्योग, टैरिफ मद 7227 9030 के अंतर्गत आने वाली वाल बीयरिंग कोटि के वायर रॉड्स और टैरिफ मद 7227 9040 के अंतर्गत आने वाली कोल्ड हैडिंग कोटि के वायर रॉड्स निर्मित कर रहा है।
- (3) वर्तमान आवेदन-पत्र सीमा-शुल्क टैरिफ के टैरिफ शीर्ष 7213 और 7227 के अंतर्गत आने वाले क्वायल रूप में वायर रॉड्स से संबंधित है। वर्तमान आवेदन-पत्र में टैरिफ शीर्ष 7214 और 7228 के अंतर्गत आने वाले सीधी लम्बाई की बार्स और रॉड्स शामिल नहीं हैं।

- (4) टैरिफ मद 7227 9090 अवशिष्ट शीर्ष ("अन्य") है और इसके कार्य-क्षेत्र में व्यापक श्रृंखला के उत्पादों को शामिल किया जाता है। टैरिफ शीर्ष 7227 9090 के अंतर्गत आने वाली वायर रॉड्स को बाहर रखे जाने के हितबद्ध पक्षकारों के दावे पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि हितबद्ध पक्षकार स्पष्ट रूप से यह विनिश्चित नहीं कर दें कि किस ग्रेड को बाहर रखे जाने की आवश्यकता है।
- (5) टैरिफ मद 7229 9090 के अंतर्गत आने उत्पादों को बाहर रखे जाने के हितबद्ध पक्षकारों का दावा अप्रासंगिक है। टैरिफ शीर्ष 7229 "अन्य एल्वाय स्टील की वायर" से संबंधित है। वर्तमान जांच में केवल वायर रॉड्स शामिल हैं और न कि वायर।
- (6) हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 14 एमएम के व्यास तक सीमित रखा जाए क्योंकि घरेलू उद्योग के पास 14 एमएम से अधिक व्यास की संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने की क्षमता विद्यमान है। हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग को 14 एमएम से अधिक व्यास के विचाराधीन उत्पाद के आर्डर दिए हैं और घरेलू उद्योग उनकी आपूर्ति करने में विफल रहा है।
- (7) घरेलू उद्योग 6-8 पीपीएम स्तर से कम ऑक्सीजन युक्त रॉड्स का निर्माण कर रहा है।
- (8) घरेलू उद्योग 100 के 6 ग्रेड के एल्वाय स्टील के रॉड्स का निर्माण कर रहा है।

12. इस तर्क के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद अत्यधिक व्यापक और अस्पष्ट है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों और घरेलू उद्योग के उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन उत्पाद को उपयुक्त रूप से परिभाषित किया गया है। प्राधिकारी ने उत्पाद के दायरे को तय करने से पहले सभी पक्षकारों के तर्कों की पूर्णरूप से जांच की है।

13. समान वस्तु के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है "समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं"। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग के उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है तथा दोनों ही उत्पाद वास्तविक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानदण्डों के संदर्भ में तुलनीय है। याचिकादाताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है तथा दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर रहे हैं। प्राधिकारी का मानना है कि आवेदकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद, संबद्ध देश से भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु हैं।

14. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद की संपुष्टि निम्नानुसार की जाती है:-

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ऑयरन अथवा नॉन-एल्वाय स्टील अथवा एल्वाय स्टील के अनियमित रूप से वाउंड क्वाईल्स बार्स और रॉड्स और हॉट रोल्ड है (जिन्हें सामान्यतया वायर रॉड्स के रूप में जाना जाता है)।

ये उत्पाद मुख्य और गैर-मुख्य श्रेणी के हैं और सभी आकारों के हैं। ये उत्पाद स्टील्स की विभिन्न गुणक्षमताओं को पूरे करते हैं, जिनमें सभी निहित होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोड तक सीमित होते हैं, फ्री कटिंग, डलाई, कॉल्ड हैडिंग, कम/मध्यम/अधिक कार्बन स्टील्स, ड्राईंग, बाल बीयरिंग स्टील, केस हार्डनिंग, स्प्रिंग स्टील, जंग-रोधी स्टील, विदरिंग स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील और अनेक अन्य कोटि की स्टील तक ही सीमित नहीं है। तथापि, निम्नोक्त उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जाता है।

(क) *इंडेंटेशन सहित बार्स और रॉड्स, रिब्स, गून्स अथवा अन्य डिफोरमेशन जो कि रोलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पादित होते हैं, जो कि टैरिफ मद 721310990 के अंतर्गत आते हैं (जिन्हें सामान्यतया रिबार्स अथवा टीएमटी बार्स के नाम से जाना जाता है)।*

(ख) टैरिफ शीर्ष 7221 के अंतर्गत आने वाले बार्स और रॉड्स।

(ग) टैरिफ शीर्ष 72271000 के अंतर्गत आने वाले तीव्र गति के स्टील के बार्स और रॉड्स।

15. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग अनेक अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव संघटक, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फास्टनर्स जिनमें नट और बोल्ट्स, कीलें, रेलवे स्लीपर्स, सामान्य अभियांत्रिकी, निर्माण उद्योग के लिए बाईंडिंग वायर्स, आर्मर्ड केबिल्स आदि शामिल हैं।

16. विचाराधीन उत्पाद को सीमा-शुल्क टैरिफ शीर्ष 7213 और 7227 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. गोपनीयता

ग 1. घरेलू उद्योग के आधार के बारे में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. अत्यधिक गोपनीयता के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:-

- (क) आईबीआईएस से प्राप्त किए गए मूल/अपरिष्कृत कारोबार-वार आयात के आंकड़ों की प्रति एक्सिस फाईल प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की गई है।
- (ख) आवेदक से भिन्न अन्य घरेलू उत्पादक के कंपनी-वार उत्पादन और बिक्रियों की मात्रा के ब्यौरे प्रदान नहीं किए गए हैं।
- (ग) संरचित मूल्य के साथ-साथ सामान्य मूल्य के मद-वार ब्यौरों को गोपनीय रखा गया है और यहां तक कि सामान्य मूल्य की शृंखलाएं नहीं बताई गई हैं।
- (घ) घरेलू उद्योग ने उसके द्वारा कारखाना-गत निर्यात कीमत का आकलन करते समय समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़े, हैंडलिंग प्रभारों और वाट समायोजन के लिए किए गए समायोजन के दावों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- (ङ) यह निवेदन किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता बना कर रखी हुई है, जिससे हितबद्ध पक्षकारों को सार्थक टिप्पणियां देने से वंचित रखा गया है, जो कि पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित गोपनीयता के प्रावधानों के पूर्णतया विरुद्ध है।
- (च) आवेदक उद्योग ने बिक्री कीमत, उत्पादन की लागत, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, उत्पादकता, रोजगार, कार्यशील पूंजी का परिकलन, आवधिक ऋणों पर ब्याज, मूल्य ह्रास, विविध आय, क्रय और बिक्रियों की नीति, मालसूची का मूल्यांकन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया आदि जैसा कोई भी औचित्य पूर्ण कारण बताए बिना सूचना की पर्याप्त गोपनीयता बनाए रखी हुई है। यह नियमावली के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों से देखा जा सकता है।
- (छ) पाटन-रोधी प्राधिकारी ने बताया है कि उन्होंने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है, लेकिन प्रारंभिक जांच परिणाम के साथ डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
- (ज) प्राधिकारी ने जेपीसी के आंकड़ों पर घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करने में विफल रहे हैं कि जेपीसी के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

ग 2. घरेलू उद्योग के विचार

18. कुछ हितबद्ध पक्षकारों का यह विचार है कि घरेलू उद्योग ने (1) आईबीआईएस के आयात के आंकड़ों, (2) कंपनी-वार उत्पाद और बिक्रियों की मात्रा के ब्यौरों, (3) संरचित सामान्य मूल्य के मद-वार ब्यौरों, (4) समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय आदि, (5) घरेलू बिक्रियों की कीमतों, (6) प्रतिशत रूप में लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, (7) संरचित सामान्य मूल्य आदि को गोपनीय रख कर याचिका में अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखी है। घरेलू उद्योग उपरोक्त तर्कों को पूर्णतया नकारता है और उनके प्रति आपत्ति दर्ज करता है। सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाता है कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में पक्षकार को यह अनुमति प्राप्त है कि वह सूचना की गोपनीयता का दावा कर सकता है। इसके अतिरिक्त नियम 7 में यह अधिदेश है कि गोपनीय सूचना के अगोपनीय वृत्तान्त का संक्षिप्त विवरण हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया जाए और जहां

ऐसा करना संभव नहीं है वहां ऐसे कारण बताए जाने चाहिए कि ऐसा संक्षिप्त विवरण प्रदान करना क्यों संभव नहीं है। घरेलू उद्योग ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 का अनुपालन करते हुए कुछ आंकड़ों की गोपनीयता का दावा किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के उपरोक्त तर्क कोई मायने नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस जांच के लिए आयात के आंकड़े पहले से ही सार्वजनिक फाइल पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए आयात के आंकड़ों की अनुपलब्धता का तर्क निराधार है।

19. इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने याचिका में प्रयुक्त किए गए जेपीसी के आंकड़ों की गोपनीयता का कोई दावा नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन की मात्राओं का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ जेपीसी के आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्रयुक्त किए गए जेपीसी के संपूर्ण आंकड़े याचिका में प्रदान किए गए हैं और यहां तक कि उन्हें सूचीबद्ध भी नहीं किया गया है।

ग 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

20. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

21. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका तदनुसार निदान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया है।

घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार

22. पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

23. वर्तमान मामले में आवेदन-पत्र मेसर्स स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, मेसर्स ऊषा मार्टिन लिमिटेड और मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त उत्पादकों का उत्पादन

भारत में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है। मेसर्ज टाटा स्टील लिमिटेड और मेसर्ज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड नामक दो अन्य घरेलू उत्पादकों ने भी इस आवेदन-पत्र का समर्थन किया है।

घ 1. घरेलू उद्योग के आधार के बारे में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. आवेदक उत्पादक कुल घरेलू उत्पादन का मात्र 40% भाग का उत्पादन करते हैं और वे पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। प्राधिकारी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के कार्यालय से अन्य उत्पादकों के उत्पादन से संबंधित सूचना भी मंगाई जानी चाहिए। कुल उत्पादन का मात्र 40% भाग किसी भी तरीके से नियम 2 (ख) की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। 40% घरेलू उत्पादन के आधार पर क्षति की जांच करना क्षति की विकृत क्षति प्रस्तुत करेगा और प्राधिकारी को अन्य उत्पादकों से सूचना प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए ताकि उत्पादन का कम से कम 50% भाग बन सके।

25. मेसर्ज टाटा स्टील लिमिटेड और मेसर्ज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड नामक दो समर्थकों ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया है, लेकिन उपरोक्त समर्थकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित सूचना के बारे में कोई प्रकटन नहीं किया गया है। आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने से पहले उसके समर्थन में पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। नियम 5 (3) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदन-पत्र को कोई भी समर्थन, डीजीएडी के समक्ष आवेदन-प्रस्तुत किए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

26. मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड आवेदन-पत्र के पृष्ठ 93 पर संबद्ध वस्तुओं का एक आयातक है।

घ 2. घरेलू उद्योग के विचार

27. घरेलू उद्योग के आधार के बारे में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है, जैसा कि मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र के साथ प्रदत्त प्रमाण पत्र से स्पष्ट प्रतीत होता है।
- (ख) आवेदन-पत्र के पृष्ठ 93 पर ज्ञात आयातकों की सूची में मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड का उल्लेख किया जाना एक लिपिकीय त्रुटि मात्र है।
- (ग) पाटन-रोधी नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान निहित नहीं है, जिससे यह अधिदेश हो कि कुल भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक का अंशदान करने वाले घरेलू उत्पादकों को पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की मांग में सहभागी होना आवश्यक है।

घ 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

28. घरेलू उद्योग के आधार के बारे में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

- (क) पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-
“(ख) ‘‘घरेलू उद्योग’’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘‘घरेलू उद्योग’’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।
- (ख) आवेदन-पत्र मेसर्ज स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेसर्ज राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड और मेसर्ज जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त चार उत्पादकों का उत्पादन, कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है। मेसर्ज टाटा स्टील लिमिटेड और मेसर्ज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड नामक दो अन्य घरेलू उत्पादकों ने भी इस आवेदन-पत्र का समर्थन किया है।

- (ग) मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों के बारे में प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया जाता है कि मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है, जैसा कि मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र के साथ प्रदत्त प्रमाण पत्र से स्पष्ट प्रतीत होता है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किया गया है, आवेदन-पत्र के पृष्ठ 93 पर ज्ञात आयातकों की सूची में मेसर्ज ऊषा मार्टिन लिमिटेड का उल्लेख किया जाना एक लिपिकीय त्रुटि मात्र है।
- (घ) इस मुद्दे के संबंध में कि आवेदक उत्पादक, कुल घरेलू उत्पादन का मात्र 40% भाग का उत्पादन करते हैं और वे पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का तात्पर्य ऐसे घरेलू उत्पादकों से है, जिनका सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है। प्रयुक्त किया गया शब्दांश "प्रमुख भाग" है, न कि "अधिकांश भाग"। अभिव्यक्ति संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि आवेदकों के उत्पादन के भाग को प्रमुख भाग बनने के लिए कुल घरेलू उत्पादन का 50% अथवा उससे अधिक होना चाहिए। ऐसे निर्णय हैं, जिनमें कुल उत्पादन के 50% से भी कम उत्पादन, नियमावली के अंतर्गत प्रमुख भाग की आवश्यकता को पूरा करेंगे।
- (ङ) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 में उल्लिखित स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि आवेदन-पत्र, घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया माना जाएगा, यदि उसका समर्थन ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा किया जाता है, जिनका सामूहिक उत्पादन, घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन का पचास प्रतिशत से भी अधिक बनता है, जो कि जैसा भी मामला हो, आवेदन-पत्र का समर्थन करते हैं अथवा उसका विरोध करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी घरेलू उत्पादक द्वारा वर्तमान आवेदन-पत्र का कोई विरोध नहीं किया गया है।
- (च) इसके अतिरिक्त प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि समर्थकों के साथ याचिकादाताओं का उत्पादन में अंशदान, वायर रॉड्स के कुल भारतीय उत्पादन का 65% है, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण मी. टन में	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015 -दिसंबर 2015 (वार्षिकीकृत)	जांच अवधि (जुलाई 2015- दिसंबर 15)	जांच अवधि (वार्षिकीकृत)
याचिकादाता						
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	***	***	***	***	***	***
स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	***	***	***	***	***	***
जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	***	***	***	***	***	***
ऊषा मार्टिन लिमिटेड	***	***	***	***	***	***
याचिकादाताओं का कुल उत्पादन	1,477,972	1,609,278	1,503,065	1,780,457	903,145	1,806,291
समर्थकों का कुल उत्पादन	1,006,800	1,037,081	1,034,350	1,102,147	556,268	1,112,536
अन्य उत्पादक	1,090,931	1,571,109	1,461,720	1,603,483	781,026	1,562,052
कुल घरेलू उत्पादन	3,575,703	4,217,468	3,999,134	4,486,087	2,240,439	4,480,879
याचिकादाताओं का अंशदान	41%	38%	38%	40%	40%	40%
याचिकादाताओं और समर्थकों का अंशदान	69%	63%	63%	64%	65%	65%

तदनुसार आवेदकों का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन को प्रमुख अंशदान बनता है और इसलिए प्राधिकारी समर्थकों द्वारा किए गए आयातों के बारे में दिए गए तर्कों पर विचार करना उपयुक्त नहीं समझते हैं।

29. इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदकों का भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है और जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित घरेलू उद्योग के आधार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग बनते हैं।

ड. न्यूनतम सीमाएं

30. वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से प्राप्त हुए आयात के आंकड़ों और संबद्ध देश से सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों को न्यूनतम स्तर से अधिक पाया गया है।

च. विविध मुद्दे

31. वर्तमान जांच के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनेक मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें पाटन का निर्धारण करने की कार्यप्रणाली और घरेलू उद्योग की क्षति के दावे शामिल हैं। जबकि पाटन और क्षति का निर्धारण करने से संबंधित मुद्दों का निदान उपयुक्त स्थानों पर कर दिया गया है, पक्षकारों द्वारा जांच के बारे में उठाए गए सामान्य मुद्दों की जांच यहां की गई है। संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

च 1. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्दे

- (क) प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य से संतुष्ट होने के तुरंत बाद एसोसिएशन सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी नहीं की थी। यह एडीए के अनुच्छेद 12.1 का उल्लंघन है। जैसा कि पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत अधिदेश दिया गया है, आवेदन-पत्र का विरोध करने के लिए भारत में घरेलू उत्पादकों को आवेदन-पत्र का प्रकटन करने में प्राधिकारी विफल रहे हैं।
- (ख) उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं की अधिकतर खपत केप्टिवली की जाती है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे याचिकादाताओं से उनके आंकड़े एकत्रित करें।
- (ग) विचाराधीन उत्पाद में व्यापक श्रृंखला के उत्पाद शामिल हैं जिनकी कीमत और लागत में अत्यधिक अंतर होता है। घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखी है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त कीमत संबंधी सूचना कोई सार्थक टिप्पणी देना बाधित करती है।
- (घ) बाल और रोलड बीयरिंग एसोसिएशन ने निवेदन किया है कि आवेदकों द्वारा सूचित किए गए आयातों की मात्राओं और एसोसिएशन द्वारा छांटे गए आंकड़ों के बीच व्यापक अंतर है। यह अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण करने के लिए विचारित आयातों के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। आवेदकों ने आईबीआईएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है, जो कि भारत के व्यापार के सांख्यिकीय और वाणिज्यिक सूचना का संग्रहण, संकलन और प्रसारण करने के लिए अधिदेश प्राप्त संगठन डीजीसीआईएंडएस द्वारा अधिप्रमाणित नहीं हैं।
- (ङ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को मूल सीमा-शुल्क ("बीसीडी") में वृद्धि करने और न्यूनतम आयात कीमत ("एमआईपी") लागू करने के रूप में अनेक संरक्षण प्रदान किए गए हैं।
- (च) जांच अवधि और क्षति अवधि, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई समस्त विगत पद्धतियों का विचलन है। संबद्ध जांच में जांच अवधि को छः महीनों के लिए लिया गया है, जो कि विश्व व्यापार संगठन की पाटन-रोधी समिति की सिफारिश (समिति द्वारा 5 मई, 2016 को अपनाई गई जी/एडीपी/6) के विपरीत है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच अवधि को 6 जून, 2016 तक बढ़ाए जाने पर विचार करें। चयनित जांच अवधि व्यापार सूचना संख्या 2/2004 से असंगत है। जांच अवधि तथा अप्रैल, 2015 और दिसंबर, 2015 के बीच पूर्णतया अधिव्याप्ति है, जिसे तुलना करने के लिए विगत वर्षों के लिए एक अवधि के रूप में प्रदान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यत भी तर्क दिया है कि विगत जांच अवधि की प्रवृत्तियों की जांच की जानी चाहिए।
- (छ) क्षति रहित कीमत का परिकलन करने के लिए नियोजित पूंजी पर 22% का प्रतिलाभ बहुताधिक है। इस संबंध में ब्रिजस्टोन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय पर विश्वास किया गया है।
- (ज) संबद्ध वस्तुओं के पाटन का कोई इतिहास नहीं है क्योंकि भारत में कभी भी ऐसी कोई जांच शुरू नहीं की गई है। इसलिए पाटन का कोई इतिहास नहीं होने के कारण वर्तमान जांच में पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क लागू नहीं किया जा सकता है।

- (झ) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने आरआईएनएल द्वारा दिनांक 25 मई, 2016 की याचिका में प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र की परिशुद्धता की ओर ध्यान आकर्षित किया है और जब कि यह जांच 2 जून, 2016 को शुरू की गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि याचिका प्रस्तुत किए जाने से मात्र 7 दिनों में यह जांच शुरू कर दी गई है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्राधिकारी ने अत्यधिक जल्दबाजी से कार्रवाई शुरू की है।
- (ञ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए भ्रामक आंकड़ों और प्राधिकारी द्वारा आंकड़ों का अनुचित मूल्यांकन किए जाने के कारण जांच की शुरुआत करना कानून की दृष्टि से निकृष्ट है।

च 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विविध निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) मूल सीमा-शुल्क में वृद्धि करना भारत सरकार द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय है। मूल सीमा-शुल्क में वृद्धि करना क्षति पहुंचाने वाले पाटन को दूर करने के लिए एक उपाय नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऑयरन और स्टील उत्पादों पर लगाई गई न्यूनतम आयात कीमत, अब 4 फरवरी, 2017 से लागू नहीं है। इसलिए वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तुएं न्यूनतम आयात कीमत के अध्वधीन नहीं हैं।
- (ख) कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि क्षति रहित कीमत का परिकलन करने में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ यथोचित नहीं है। घरेलू उद्योग उपरोक्त तर्क का सुदृढता से खंडन करता है और उसका निवेदन है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ क्यों यथोचित नहीं है। वास्तव में सेस्टेट ने हाल ही के दो निर्णयों में यह पाया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ वैध है और इसका खंडन करने वाले पक्षकार का यह दायित्व है कि वह ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे कि नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ क्यों यथोचित नहीं है। इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान सेस्टेट के मेरिनो पेनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में दिनांक 27 नवंबर, 2015 के अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53541/2015-सीयू (डीबी) और एक्सिम कोर्प इंडिया प्राईवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में दिनांक 12 सितंबर, 2016 के अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53462/2016-सीयू (डीबी) की ओर आकर्षित किया जाता है। सेस्टेट के उपरोक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ वैध है और इसकी संपुष्टि अंतिम जांच परिणाम में भी सुनिश्चित रूप से की जानी चाहिए।
- (ग) अधिनियम की धारा 9 क (3) में उत्पाद के पाटन के इतिहास से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। याचिकादाताओं का प्राधिकारी से अनुरोध है कि संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाए क्योंकि पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की शर्त पूर्णतया पूरी होती है।
- (घ) संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने का साक्ष्य विद्यमान है जो कि इस तथ्य से पता चलता है कि आस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका आदि सहित अनेक देशों ने चीन जनवादी गणराज्य से वायर रॉड्स के आयातों के खिलाफ पाटन-रोधी जांच शुरू कर दी है। अल्प अवधि में भारत में विचाराधीन उत्पाद का व्यापक पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- (ङ) निर्यातक पूर्णतया अवगत हैं कि वे पाटन कर रहे हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतों में अत्यधिक कमी हुई है, जैसा कि संबद्ध देश के लिए पहुंच मूल्यों से पता चलता है।

च 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विविध निवेदनों की जांच की गई है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

- (क) इस निवेदन के संबंध में कि प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना जारी नहीं की है, प्राधिकारी की यह प्रथा है कि केवल जांच शुरू करने के समय केवल ज्ञात पक्षकारों को ही सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 12.1 के अंतर्गत प्राधिकारी को जांच करने वाले प्राधिकारियों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करना अपेक्षित होता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार, जो कि प्राधिकारी को जांच शुरू करने के समय ज्ञात नहीं है, अनुरोध कर सकता है और आवेदन-पत्र का अगोपनीय वृत्तान्त प्राप्त कर सकता है।

- (ख) केप्टिव खपत के मुद्दे संबंध में प्राधिकारी ने केप्टिव खपत को आवेदन-पत्र से पहले ही प्राप्त कर लिया है।
- (ग) इस मुद्दे के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद में व्यापक श्रृंखला के उत्पादों को शामिल किया गया है, जिनकी कीमत और लागत में अंतर है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद केवल वायर रॉड है और उसकी कीमत और लागत में अंतर होने का कारण केवल विभिन्न ग्रेड और आकारों में विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता है।
- (घ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, भारत के लिए उत्पादन की मात्रा के आंकड़े जेपीसी के आंकड़ों से प्राप्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (ङ) हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग अत्यधिक संरक्षण प्राप्त कर रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग को मूल सीमा-शुल्क ("बीसीडी") में वृद्धि करने और न्यूनतम आयात कीमत ("एमआईपी") लागू करने के रूप में अनेक संरक्षण प्रदान किए गए हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि -
- (1) मूल सीमा-शुल्क में वृद्धि करना भारत सरकार द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय है। मूल सीमा-शुल्क में वृद्धि करना, क्षति पहुंचाने वाले पाटन को दूर करने के लिए एक उपाय नहीं माना जा सकता है।
 - (2) न्यूनतम आयात कीमत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अस्थायी उपाय था और यह संबद्ध वस्तुओं के लिए 4 फरवरी, 2017 तक लागू था।
- (च) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।
- (छ) इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि 6 महीनों से अधिक होनी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी प्रथाओं से संबंधित समिति की सिफारिश (विश्व व्यापार संगठन का दस्तावेज संख्या जी/एडीपी/ 6 दिनांक 16 मई, 2000) के अनुसार ऐसा उल्लेख है कि -
- "....पाटन संबंधी जांच के लिए आंकड़ों का संग्रहण करने की अवधि सामान्यतया 12 महीनों की होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में यह जांच शुरू करने की तारीख के समाप्त होने पर छः महीनों से कम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि व्यवहार्य है।"*
- (ज) इसलिए उपरोक्त सिफारिश को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि को 6 महीनों की अवधि माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने अनेक अन्य जांच में भी जांच अवधि 6 महीने की तय की है। साथ ही प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच की शुरुआत, किसी भी तरीके से व्यापार सूचना संख्या 2/2004 को उल्लंघन नहीं है।
- (झ) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि जांच अवधि पश्चात विद्यमान प्रवृत्तियों की जांच की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में जांच अवधि पश्चात विद्यमान प्रवृत्तियां संबद्ध नहीं हैं। पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार शुरू की जाने वाली पुनरीक्षाओं के मामले में जांच अवधि पश्चात विद्यमान प्रवृत्तियां संबद्ध हो जाती हैं क्योंकि यदि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्राधिकारी के लिए पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करनी आवश्यक होती है।
- (ञ) पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के अनुरोध के संबंध में सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क (3) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

यदि सरकार का ऐसी पाटित वस्तु के संबंध में जिसके कारण क्षति हो रही है, यह विचार है कि -

- i. ऐसे पाटन का इतिहास रहा है जिसके कारण क्षति हुई है अथवा आयातक इस तथ्य से अवगत था अथवा अवगत होना चाहिए था कि निर्यातक पाटन करने की प्रक्रियाएं अपना रहा है और ऐसे पाटन के कारण क्षति होगी और
- ii. अपेक्षाकृत अल्प समय में आयातित ऐसी वस्तु के व्यापक पाटन होने के कारण क्षति हो रही है, जो कि समय और पाटित आयातित वस्तु की मात्रा तथा अन्य परिस्थितियों के आलोक में लागू किए जाने वाले पाटन-रोधी शुल्क के उपचारी प्रभाव को गंभीर रूप से कम करेगी, तो -

केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उप-धारा (2) के अंतर्गत लागू किए जाने वाले पाटन-रोधी शुल्क को लागू किए जाने की तारीख से पूर्व तारीख से पाटन-रोधी शुल्क लागू कर सकती है, लेकिन उप-धारा के अंतर्गत ऐसी अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिनों के बाद नहीं और उस समय लागू किसी विधि में निहित कोई भी प्रावधान होने के बावजूद ऐसा शुल्क ऐसी दर से और ऐसी तारीख से लागू होगा, जो कि अधिसूचना में विनिश्चित होगा।

- (ट) मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस मामले में पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करना उचित नहीं समझते हैं।
- (ठ) वर्तमान जांच की शुरुआत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों का प्रथम दृष्टया विश्लेषण करने के आधार पर की गई है, जिससे ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण आवेदकों को क्षति हो रही है और इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध है। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए भ्रामक आंकड़ों और प्राधिकारी द्वारा आंकड़ों का अनुचित मूल्यांकन किए जाने के कारण जांच की शुरुआत करना कानूनी रूप से निकृष्ट है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के समय याचिकादाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर सूचना की परिशुद्धता और पर्याप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया वे स्वयं संतुष्ट हुए हैं।

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

33. सामान्य मूल्य के संबंध में धारा 9 क (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री औष्र सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।”

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के संबंध में प्रावधान

34. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

8 (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश" शब्द का अर्थ ऐसा कोई देश है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी ने लागत या कीमत निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर प्रचालन करते हुए निर्धारित नहीं किया है क्योंकि ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार पण्य वस्तुओं का उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करती हैं।

(2) ऐसी एक परिकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच से पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में निर्धारित किया गया है या माना गया है, को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा;

बशर्ते कि तथापि यह कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश ऐसे देश की संबंधित फर्मों निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस आशय की सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराके ऐसी किसी परिकल्पना का खंडन कर सकते हैं जो यह सिद्ध करती हो कि वह देश उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या :-

(क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

(ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;

(ग) इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

बशर्ते कि फिर भी जहां इस पैरा में विनिश्चित मानदंड के आधार पर लिखित साक्ष्य द्वारा ऐसा दर्शाया गया है कि एक अथवा अधिक ऐसी फर्मों के लिए पाटन-रोधी जांच के अध्यधीन बाजार की दशाएं विद्यमान हैं, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पैराग्राफ 7 और इस पैराग्राफ में उल्लिखित सिद्धांतों के बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदन:

35. एम.ई.टी. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए एवं प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक समझे गए विभिन्न निवेदनों की जांच की जाती है और निम्नानुसार समाधान किया जाता है:-
- (क) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय चीन के उत्पादकों के विक्रय मूल्य और लागत के बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य डब्ल्यूटीओ के अपने स्वीकृति प्रोटोकॉल के अनुसार वर्ष 2016 में बाजार अर्थव्यवस्था में पहुंचा है।
- (ख) आवेदकों ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 (7) का उल्लंघन करते हुए चीन में निर्मित मूल्य अथवा भारत के लिए किसी अन्य तृतीय देश से कीमत के बारे में विचार किए बिना ही सीधे सामान्य मूल्य निर्मित किया है। शेनयांग मत्सुशिता एस. बैट्री कंपनी लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. एवं अन्य के मामले में रिलायंस को शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर छोड़ दिया है जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 (7) में उल्लिखित विभिन्न पद्धतियों को अनुवर्ती रूप से लागू करने के बाद में सामान्य मूल्य का निर्धारण करना होता है।
- (ग) याचिकाकर्ताओं ने डी.आई. की लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य के बारे में विचार किया है। प्राधिकारी की निरन्तर प्रक्रिया के आधार पर सबसे कुशल उत्पादक की लागत पर ही विचार करना चाहिए।
- (घ) प्राधिकारी ने अलग-अलग अवधियों के निर्यात कीमत एवं सामान्य मूल्य के आंकड़ों को स्वीकार करके ए.डी.ए के अनुच्छेद 5.3 का उल्लंघन किया है। एक ही समय अवधि में की गई विक्रयों के संबंध में निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच में तुलना करके प्राधिकारी ने पाटन मार्जिनों का निर्धारण नहीं किया है। आवेदकों ने प्रकट नहीं किया है कि क्या सामान्य मूल्य का निर्धारण पीओआई के लिए किया है अथवा किसी अन्य अवधि के लिए किया है।
- (ङ) जियांग्सु शानगेंग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. (जियांग्सु) ने उसके प्रश्नावली प्रत्युत्तर को स्वीकार करने के लिए तथा अपनी आपूर्ति चैन (शृंखला) के लिए अलग पाटन मार्जिन की गणना करने हेतु प्राधिकारी से अनुरोध किया है क्योंकि परिशिष्ट- 2 में आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए उसके संबंधित उत्पादकों पर कोई बाध्यता नहीं है। इसकी वजह से उन्होंने भारत को निर्यात नहीं किया है। इसके अलावा, जियांग्सु ने यह निवेदन किया है कि प्राधिकारी ने जियांग्सु शागनाग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लि. की ओर से दायर किए गए प्रश्नावली प्रत्युत्तरों को मनमाने ढंग से निरस्त कर दिया है क्योंकि असंबद्ध व्यापारियों ने सूचना प्रस्तुत नहीं की है तथा तदनुसार "तथ्य उपलब्ध" के अनुसार आवेदन किया है।
- (च) बेंक्सी बीटाई गोआसू स्टील वायर रोड कंपनी लि. ("बी.बी.जी.") ने यह निवेदन किया है कि उसके संबंधित निर्यातक मै0 निंगबो सिमी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि. (निंगबो) के प्रत्युत्तर को दायर न करने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत के लिए उसके कुछ निर्यातों के संबंध में भारत के लिए निंगबो के माध्यम से निर्यातों की मात्रा अपर्याप्त है। इसके अलावा, निंगबो ने 4.11.2017 को अपना विलम्बित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि बी.बी.जी. की संबंधित निर्यातक बेंक्सी बीचिंग आयरन एण्ड स्टील ग्रुप इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लि. चीन (बी.बी.आई.ई.) के द्वारा परिशिष्ट 2 में विक्रयों के बारे में सूचित न करने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बी.बी.जी. द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर के भाग के रूप में उपलब्ध परिशिष्ट 2 में उसने इन व्यौरों के बारे में सूचित किया है और बी.बी.आई.ई. उसके उत्पादक बी.बी.जी. के लिए निर्यात एजेंसी के रूप में ही कार्य कर रही है। उपरोक्त के दृष्टिगत बी.बी.जी. ने उसके प्रश्नावली प्रत्युत्तर को स्वीकार करने तथा उसकी आपूर्ति चैन (शृंखला) के लिए अलग पाटन मार्जिन की गणना करने हेतु प्राधिकारी से अनुरोध किया है।
- (छ) जियांगजिन जिंगचेंग अल्लाय मैटीरियल कंपनी लि. ("जे.एक्स.ए.एम.") उत्पादक और जियांगजिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लि. ("जे.एक्स.एस.एस.") निर्यातक ने यह निवेदन किया है कि उत्पादक और निर्यातक संबंधित पक्षकार होते हैं और उत्पादक ने डुप्लीकेट दायर होने की स्थिति से बचने के लिए संबंधित निर्यातक के द्वारा दायर किए गए परिशिष्ट 2 का उल्लेख किया। क्योंकि भारत के लिए निर्यातों के बारे में प्रासंगिक आंकड़े की अभिरक्षक कंपनी निर्यातक होता है। उपर्युक्त के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से परिशिष्ट 2 एक बार दोबारा दायर किया गया था, लेकिन पी.एफ. से एक सप्ताह पूर्व दायर किया गया था। उपरोक्त के दृष्टिगत, जे एक्स ए एम और जे एक्स एस

एस के द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर को इस वजह से निरस्त नहीं करना चाहिए कि उत्पादक ने ई.क्यू प्रत्युत्तर में परिशिष्ट उपलब्ध नहीं कराया है।

- (ज) ई.क्यू प्रत्युत्तर दायर करने की प्रारंभिक 40 दिनों की समय अवधि समाप्त होने बाद हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा दायर परिशिष्ट 2 प्राधिकारी के द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए।

घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए निवेदन:-

36. जांच के दौरान एम.ई.टी., सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए एवं प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए विभिन्न सामान्य निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- (क) हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किया गया यह दावा गलत है कि ई.सी फॉसनर में अपीलीय निकाय ने स्वतः ही बाजार अर्थव्यवस्था स्तर प्राप्त करने हेतु चीन के लिए सशक्त औचित्य उपलब्ध कराया है। अपीलीय निकाय रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। अपीलीय निकाय रिपोर्ट को 28 जुलाई, 2011 को, अर्थात् 11 दिसंबर 2016 की समाप्ति तारीख से 5 वर्ष पहले डब्ल्यू टी ओ डी एस बी के द्वारा स्वीकार किया गया था। ई.यू. फॉसनर में, चीन जनवादी गणराज्य मूल के कुछ लौह अथवा इस्पात के फॉसनरों के आयातों पर ई.सी के द्वारा निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने को WTODSB से पूर्व चुनौती दी जा रही थी। स्पष्टतः एक बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में चीन की स्थिति से संबंधित मुद्दा WTO अपीलीय निकाय के समक्ष नहीं था। हितबद्ध पक्षकारों ने भी अपने इस दावे के समर्थन में अपीलीय निकाय रिपोर्ट से किसी विशिष्ट टिप्पणी भी नहीं दर्शायी है जिससे चीन जनवादी गणराज्य को स्वतः ही बाजार अर्थव्यवस्था स्तर प्रदान करने के लिए अपीलीय निकाय के द्वारा सशक्त औचित्य उपलब्ध कराया था।
- (ख) चीन का स्वीकृति प्रोटोकॉल में यह प्रावधान नहीं है कि चीन को 15 वर्षों के बाद स्वतः ही बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर मिल जाएगा। इसमें केवल यह कहा है कि पैरा 15 (क) (ii) के बहुत विशिष्ट प्रावधान लागू होने समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 15 के अन्य भाग (अनुच्छेद 15 (क) (i) सहित) लागू रहेंगे। अनुच्छेद 15 (क) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आयातक WTO सदस्य जांच के अधीन उद्योग के लिए या तो चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो घरेलू कीमतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो। अनुच्छेद 15 (क) (i) में यह भी प्रावधान है कि चीन की कीमतों अथवा लागतों का उस स्थिति में उपयोग किया जाएगा यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध कर सकता है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ प्रचलन में हैं। स्वीकृति प्रोटोकॉल के स्पष्ट प्रावधानों के होते हुए हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा दी गई इस व्याख्या कि 15 वर्षों के बाद चीन को बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में मानना चाहिए, इससे केवल प्रावधान की समाप्ति और उस बात का जानने का आरोप लग सकता है, जो है ही नहीं। यह प्रोटोकॉल के अन्य सभी प्रावधानों का भी खण्डन करता है, जो प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय सन्धि व्याख्या की नियमावली केवल ऐसी संभावना की अनुमति नहीं देती है, पैक्टाशर्टेवंडा के नियम को छोड़ता है जिस पर हितबद्ध पक्षकार अपने दावे पर अन्ततः यकीन करते हैं।
- (ग) पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 8 (4), अनुबंध-1 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थ-व्यवस्था देश के रूप में मान सकता है, जिसको डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश के द्वारा पाटनरोधी जांचों के प्रयोजनार्थ मानदण्ड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है। चीन जनवादी गणराज्य के लिए इस मानदण्ड को पूरा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है।
- (घ) वर्तमान जांच की शुरुआत करने की तारीख 2 जून, 2016 थी। चीन जनवादी गणराज्य के स्वीकृति प्रोटोकॉल में अपेक्षित समाप्ति तारीख 11 दिसंबर, 2016 है। चाहे प्रावधान की समाप्ति को हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा कथित रूप से प्रभावी बताया गया है, परन्तु इसे जांच के लिए लागू करने की भांति पूर्व-व्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, जो 11 दिसंबर, 2016 से पूर्व शुरू की गई थी।
- (ङ) चीन का कोई भी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था स्तर को पूरा नहीं कर सकता है। प्रासंगिक मानदण्ड को अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी भी डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश ने चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था स्तर प्रदान नहीं किया है।
- (च) जब तक प्रतिक्रिया देने वाले चीन के निर्यातक नियमावली के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करना अपेक्षित होता है।

- (छ) किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रतिनिधि देश के बारे में सुझाव नहीं दिया है। अतः हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों में ऐसी कोई अच्छाई नहीं है जिसको चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय प्राधिकारी द्वारा क्रमिक रूप से आगे बढ़ाना चाहिए।
- (ज) अंतिम जांच परिणामों में भी चीन के निर्यातकों के द्वारा दायर किए गए निवेदनों के बारे में लिए गए समान निर्णय की स्थिति को बनाए रखने के लिए याचिका-कर्ता प्राधिकारी से आग्रह करते हैं। उत्पादकों/निर्यातकों के द्वारा दायर किए गए अपूर्ण प्रत्युत्तरों को प्राधिकारी के द्वारा स्वीकार नहीं करना चाहिए और इन आपूर्ति चैनलों के लिए पाटन मार्जिन सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों पर आधारित होने चाहिए।
- (झ) हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा सहयोग के संबंध में घरेलू उद्योग यह भी निवेदन करता है कि अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों के द्वारा सख्त अपेक्षा सुनिश्चित की है। समतुल्य शुल्क के मामले में भारत से कुछ क्षय प्रतिरोधी इस्पात उत्पादों के आयातों के संबंध में अमरीकी यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ("यू.एस.डी.ओ.सी.") के द्वारा की गई जांच के बारे में एक निर्यातक को केवल इस वजह से असहयोगी माना है क्योंकि निर्यातक यू.एस.डी.ओ.सी. को यह सूचित करने में असमर्थ रहा है कि कच्चे माल की मात्रा की आपूर्ति करने वाली संबंधित कंपनी पी.ओ.आई. के अंतिम दो महीनों के लिए प्रचालन में थी।
- (ञ) वैश्विक प्रथा यह है कि तथ्यों को छिपाने एवं असहयोग की वजह से प्रभावली प्रत्युत्तर को निरस्त कर देना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों पर समान बंधन लगाने चाहिए और ऊपर दर्शाए गए कारणों की वजह से उन्हें असहयोगी मानना चाहिए।
- (ट) यह भी अनुरोध है कि कारखानों से बाहर निर्यात कीमत की गणना करते समय बैंक प्रभारों की जहाँ कटौती नहीं की है, वहाँ पर स्पष्ट तुलना हेतु निर्यातकों की निर्यात कीमत से बैंक प्रभारों की भी कटौती के रूप में कमी करनी चाहिए।

प्राधिकारी के द्वारा जांच

चीन के उत्पादों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दावे:-

37. चीन के स्वीकृति प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव

उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

38. अनुच्छेद 15 में यह अपेक्षा होती है कि उप-पैराग्राफों में से एक पैराग्राफ के प्रावधान चीन की स्वीकृति की तारीख से 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस उप-पैराग्राफ के प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गए। चूंकि घरेलू उपयोग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन के तथ्य जांच अवधि के आधार पर सुनिश्चित हुए हैं, इसलिए केवल जांच अवधि के दौरान ही प्रचलित परिस्थितियां वर्तमान जांच हेतु प्रासंगिक उपयुक्त और जरूरी हैं। वर्तमान समीक्षा के लिए जांच की अवधि (पी.ओ.आई.) जुलाई, 2015 से दिसंबर, 2015 है। चूंकि अनुच्छेद 15 का उप-पैराग्राफ जांच की अवधि के दौरान अस्तित्व में था, इसलिए प्राधिकारी उस स्थिति में उस पद्धति का उपयोग करने के लिए पात्र है, जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित है, यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि उस उत्पाद के विनिर्माण उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का विनिर्माण करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी परिस्थियाँ प्रचलित हैं।
39. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत 3 वर्षों में चीन जनवादी गणराज्य को भारत और अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के द्वारा पाटनरोधी जांचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। नियमावली के तहत निर्यातक देश अथवा व्यक्तिगत निर्यातकों के द्वारा अनुमान का खण्डन करने के अध्यधीन चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।
40. यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I, पैराग्राफ 8 के अनुसार यदि चीन जनवादी गणराज्य का निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर सूचना और पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराता (कराते) हैं तो गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का खण्डन किया जा सकता है। बाजार अर्थव्यवस्था ट्रीटमेंट प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/ पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों /उत्पादकों के लिए अपेक्षित है, ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदण्ड के बारे में यह विचार कर सके कि क्या:-
- (क) कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम, उत्पादन बिक्री और निवेश की लागत सहित कीमतों, लागतों एवं निवेशों के बारे में ऐसे देशों में संबंधित फर्मों के निर्णय आपूर्ति और मांग को दर्शाते हुए बाजार संकेतों के प्रत्युत्तर में तथा इस संबंध में राज्य के सार्थक हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं और क्या बृहद निवेशों की लागतें बाजार मूल्यों का काफी प्रतिबिम्बित करती है।
- (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से, विशेषकर परिसम्पत्तियों के मूल्य-ह्रास, अन्य बट्टे-खाते डालने, विनिमय व्यापार एवं ऋणों की क्षतिपूर्ति करके भुगतान के संबंध में काफी विकृतियों के अध्यधीन होती है।
- (ग) ऐसी फर्में दिवालियापन एवं सम्पत्ति संबंधी कानूनों के अध्यधीन होती हैं जो फर्मों के प्रचालनों के लिए कानूनी विश्वसनीयता एवं स्थिरता के बारे में गारंटी देता है। और
- (घ) विनिमय दर बाजार दर पर परिवर्तित की जाती है।

41. यह नोट किया है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थ-व्यवस्था ट्रीटमेंट का दावा नहीं किया है। तदनुसार प्राधिकारी को उपर्युक्त किसी मानदण्ड की जांच करना अपेक्षित नहीं है तथा उसने यह निर्णय दिया कि चीन पी.आर के उत्पादक/निर्यातक बाजार अर्थ-व्यवस्था परिस्थितियों के तहत कार्य नहीं कर रहे हैं।

सामान्य मूल्य का निर्धारण

42. प्राधिकारी ने निर्धारित कार्य और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देते हुए उन्हें प्रश्नावली भेजी थीं। निम्नलिखित पक्षकारों ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किए हैं :-

1. जियांगसु शागेंग मैटीरियल ट्रेड कं. लि. (निर्यातक)
2. बी एंड एल मैटल (हांगकांग) लि. (निर्यातक)
3. जियांगसु रनझौंग हाई टेक कं. लि. (उत्पादक)
4. झांगजीयागेंग शाजिंग स्टल कं. लि. (उत्पादक)
5. झांगजीयागेंग हांगजिंग काओजियन क. लि. (उत्पादक)
6. झांगजीयागेंग रौंगशेंग स्टील मेकिंग क. लि. (उत्पादक)
7. जिनागसु शागेंग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. (निर्यातक)
8. बी एंड एल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कं. लि. (निर्यातक)
9. झांगजीयागेंग होंग चेंग गाओजियन कं. लि. (उत्पादक)
10. झांगजियोगेंग रनझौंग स्टल कं. लि. (उत्पादक)
11. जिनशा इंटरनेशनल प्रा. लि. (निर्यातक)
12. मिनमैटल्स थिंगकोऊ मीडियम प्लेट कं. लि. (उत्पादक)
13. सिनोमैटीरियल इंटरनेशनल कं. लि. (निर्यातक)
14. मानुचर स्टल हांगकांग लि. (निर्यातक)
15. बुरविल रिसोसि लि. (निर्यातक)
16. जियांगसु योंगगेंग ग्रुप कं. लि. (उत्पादक)
17. जेनेसिस रिसोसिस कं. लि. (हांगकांग)
18. स्मार्ट टाइमिंग स्टल लि. (निर्यातक)
19. टॉपटिप होल्लिंग प्रा. लि. (निर्यातक)
20. जेनिथ स्टील ग्रुप कं. लि. (उत्पादक)
21. हांगझाऊ कोजेनेरेशन (हांगकांग) कं. लि. (निर्यातक)
22. यूनिस्टील इंटरनेशनल डी एम सी सी (निर्यातक)
23. विन फेथ ट्रेडिंग लि. (निर्यातक)
24. बेंगजी ऑयरन एण्ड स्टील हांगकांग लि. (निर्यातक)
25. बेंगजी बीइंग आयरन एण्ड स्टील ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि. (निर्यातक)
26. बेंगजी बेतई गाओसु स्टील वायर रोड कं. लि. (उत्पादक)
27. फ्यूचर मैटीरियल इण्डस्ट्री (हांगकांग) कं. लि. (निर्यातक)
28. जियांगजिन जिंगचेन अलॉय मैटीरियल कं. लि. (उत्पादक)
29. जियांगजिन जिंगचेन स्पेशनल स्टील वर्क्स क. लि. (निर्यातक)

43. इसके अलावा, निम्नलिखित निर्यातकों/ व्यापारियों ने पूर्ण प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करने के बजाय केवल परिशिष्ट-2 और 3क प्रस्तुत किए हैं :-

1. हांगकांग ग्रांड इंटरनेशनल कं. लि.
2. हियोसुंग कारपोरेशन
3. स्टीलको पेसिफिक ट्रेडिंग लि.
4. स्टीलफोर्स फॉर ईस्ट लि.
5. टाटा इंटरनेशनल मैटल्स (एशिया) लि.
6. यूनिस्टील इंटरनेशनल डी एम सी सी (अलग से प्रस्तुत)

44. यह नोट किया जाता है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था ट्रीटमेंट का दावा नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्मित सामान्य मूल्य को स्वीकार किया है।

45. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के संबंध में प्राधिकारी को ए. डी. नियमावली के अनुबंध 1(7) में उल्लिखित अलग-अलग पद्धतियों को क्रमिक रूप से अपनाने के बाद सामान्य मूल्य निर्मित करना होता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को न तो प्रतिनिधि देश के बारे में सुझाव दिया है और न ही इस संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराये हैं। इसलिए प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैराग्राफों में यथावर्णित सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है।

46. प्राधिकारी ने अलग-अलग अवधियों की निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य संबंधी आंकड़ों को स्वीकार करके ए डी ए के अनुच्छेद 5.3 का उल्लंघन किया है, इस दावे के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किया गया निवेदन सामान्य मूल्य के रूप में किसी अच्छाई से विहीन (रहित) है तथा निर्यात कीमत का निर्धारण केवल पी ओ आई के लिए किया जाता है।

सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पद्धति

47. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण प्राधिकारी के द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में घरेलू विक्रय मूल्य अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरे देश में निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित किसी अन्य देश के लिए ऐसे किसी तीसरे देश से निर्यात कीमतों के आधार पर करना होता है। तथापि, यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर बताए विकल्पों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद हेतु भारत में वास्तव में भुगतान किए गए अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकता है।

48. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं की किसी विश्वसनीय कीमत और लागत संबंधी व्यौरों के न होने की स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान किए गए अथवा देय कीमत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और इसे पाटन मार्जिन सारणी में नीचे दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

मै. बैंग्जी बीटाई गाओसु स्टील वायर रौड कं. लिमि., चीन जन. गण (उत्पादक), सम्बद्ध व्यापारियों के माध्यम से, मै. बैंग्जी आयरन एण्ड स्टील ग्रुप इम्पो. एण्ड एक्सपोर्ट कारपो. लिमि., चीन जन. गण, मै. बैंग्जी आयरन एण्ड स्टील हांगकांग लिमि. (हांगकांग) और असंबद्ध व्यापारियों, मै. अंगझाओ कोजेनेरेशन (हांगकांग) कं. लिमि. (हांगकांग), मै. विन फेथ ट्रेडिंग लिमि. (हांगकांग), मै. फ्यूचर मैटीरियल्स इण्डस्ट्री (हांगकांग) कं. लिमि. (हांगकांग), मै. निंगवो सी आई एम ई आई इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट क. लिमि., चीन (निर्यातक/ व्यापारी) और मै. यूनिस्टील इंटरनेशनल डी एम सी सी (यू. ए. ई.)।

49. मै. बेंगजी बीटाई गाओसु स्टील वायर रौड कं. लि. चीन गणराज्य (बी बी जी) के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बी. बी. जी., चीन जन गण में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। बी. बी. जी. ने अपनी संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। बी. बी. जी. ने अपनी संबद्ध कम्पनी मै. बेंगजी बीईंग आयरन एण्ड स्टील ग्रुप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि. (बी बी आई ई) को संबद्ध वस्तुएं बेची जिसने फिर संबद्ध वस्तुओं को एक अन्य संबद्ध ट्रेडिंग कंपनी मै. बेंगजी आयरन एण्ड स्टील हांगकांग लि. तथा असंबद्ध व्यापारियों मै. हांगझाओ कोजेनेरेशन (हांगकांग) क. लि. (हांगहांग), मै. विन फेथ ट्रेडिंग लि. (हांगकांग), मै. फ्यूचर मैटीरियल्स इण्डस्ट्री (हांगकांग) कं. लि., मै. यूनिस्टील इंटरनेशनल डी एम सी सी (यू ए ई), मै. निंग्वो सी आई एम ई आई इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट और मानुचार स्टील हांगकांग लि., मै. बेंगजी आयरन एण्ड स्टील हांगकांग लि. को संबद्ध वस्तुएं बेची और ऊपर बताए असंबद्ध ट्रेडरों ने भारत के लिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया।
50. बी बी जी और बी बी आई ई के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बी बी जी का एक संबद्ध ट्रेडर बी बी आई ई है और वह ग्राहक के साथ संविदाएं करता है तथा स्वयं अपने नाम से बीजक जारी करता है। तथापि, बी बी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर में यह बताया गया है कि बी बी जी की एक निर्यात एजेंसी के रूप में बी बी आई ई कार्य कर रहा है। बी बी आई ई ने पूर्ण प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और केवल परिशिष्ट 9 प्रस्तुत किया है। तथापि, बी बी जी ने इन तथ्यों को अपने लिखित निवेदनों में तदंतर स्वीकार किया है और यह नोट किया है कि इसने 1 मई, 2017 अर्थात् प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी होने के बाद बी बी आई ई के लिए परिशिष्ट-2 प्रस्तुत किया। साथ ही, बी बी जी ने अपने प्रत्युत्तर में बी बी आई ई के रूप में ग्राहक का नाम नहीं दिखाया है। तदनुसार, प्राधिकारी को यह मत है कि बी बी जी और बी बी आई ई ने ब्यौरा छिपाने एवं प्राधिकारी के समक्ष गलत ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
51. इसके अलावा, ऊपर बतायी गई कंपनियों में से मै. निंग्वो सी आई एम ई आई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ने 4 नवंबर, 2016 अर्थात् प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है और मानुचर स्टील हांगकांग लि. ने बी बी जी द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं को भारत के लिए कोई निर्यात करने की सूचना नहीं दी है। इसलिए ट्रेडर (ट्रेडरों) के द्वारा तथ्यों को छिपाने सहित बी बी आई ई से पूरी सूचना न मिलने और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनिवार्य अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद में प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत प्राधिकारी बी बी जी और उसके ट्रेडरों/निर्यातकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर को स्वीकार नहीं करता है। तदनुसार, बी बी जी के लिए निर्यात कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।
- जियांगसु रनजोंग हाई टेक. क. लिमि. झांगजियागेंग शाजिंग स्टील कं. लिमि. झांगजियागेंग हांगसिन गाओसिजन क. लिमि. झांगजियोगेंग रौंगशेंग स्टील मेकिंग क. लिमि., झांगजियोगेंग होंगचेंग गाओक्सिजन क. लिमि. और झांगजियोगेग रनजोंग स्टील क. लिमि. (उत्पादकों) ने संबद्ध ट्रेडरों जिनागसु सागेंग इंटरनेशनल ट्रेड क. लिमि., जियांगसु सागेंग मैटीरियल ट्रेड क. लिमि., जिन्शा इंटरनेशनल प्रा. लिमि. और असंबद्ध ट्रेडरों बी एंड एल मैटल (हांगकांग) लिमि., बी एंड एल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क. लिमि., हांगकांग ग्राण्ड इंटरनेशनल क. लिमि., हियोसुंग कारपोरेशन, स्टीलको पेसिफिक ट्रेडिंग लिमि., स्टीलफोर्स फॉर ईस्ट लिमि., टाटा इंटरनेशनल मैटल्स (एशिया) लिमि. और यूनिस्टील इंटरनेशनल डी एम सी सी के माध्यम से निर्यात किया।
52. उपर्युक्त कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि छः संबद्ध कंपनियों नामतः मै. जिनागसु रनझोंग हाई टेक. क. लि., झांगजियोगेंग साजिंग स्टील कं. लि., झांगजियोगेंग गाओक्सियन कं. लि., झांगजियोगेंग रेंगशेंग स्टील मेकिंग कं. लि., झांगजियोगेंग हांगचांग गाओक्सियन कं. लि. और झांगजियागेंग रनझोंग स्टील कं. लि. के द्वारा संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया गया था।
53. इन उत्पादकों के द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध ट्रेडरों नामतः मै. जिनागसु शागेंग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि., मै. जियांगसु शागेंग मैटीरियल ट्रेड कं. लि., मै. जिन्शा इंटरनेशनल प्रा. लि. और असंबद्ध ट्रेडरों नामतः मै. बी एंड एल मैटल (हांगकांग) लि. (हांगकांग), बी एंड एल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कं. लि., मै. हांगकांग ग्राण्ड इंटरनेशनल कं. लि., मै. हियोसुंग कारपोरेशन, मै. स्टीलको पैसिफिक ट्रेडिंग कं., मै. स्टीलफोर्स फॉर ईस्ट लि., मै. टाटा इंटरनेशनल मैटल्स (एशिया) लि., मै. यूनिस्टील, इंटरनेशनल डी एम सी सी, मानुचर स्टील हांगकांग लि., मै. थिस्सेनक्रूप मान्नेक्स एशिया प्रा. लि., यू आई एल हांगकांग लि., गालप रिसोसिज प्रा. लि. मै. क्यूमिक स्टील लि. और मै. स्मार्ट टाइमिंग स्टील लि. के माध्यम से निर्यात किया जाता है।

54. ऊपर बतायी कंपनियों में मै. थिस्सेनक्रूप डी एम सी सी, मानुचर स्टील हांगकांग लि., मै. थिस्सेनक्रूप मान्नेक्स एशिया प्रा. लि., यू आई एल हांगकांग लि., गालप रिसोसिज प्रा. लि. मै. क्यूमिक स्टील लि. ने कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, इन उत्पादकों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का भारत के लिए निर्यात करने के बारे में मै. स्मार्ट टाइमिंग स्टील लि. और मानुचर स्टील हांगकांग लि. ने सूचित नहीं किया है। साथ ही, मै. हांगकांग ग्राण्ड इंटरनेशनल कं. लि., मै. हियोसंग कारपोरेशन, मै. स्टील को पैसिफिक ट्रेडिंग लि. मै. स्टील फोर्स फॉर ईस्ट लि., मै. टाटा इंटरनेशनल मैटल्स (एशिया) लि. के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर मौटे तौर पर अपूर्ण हैं। इन ट्रेडरों ने केवल परिशिष्ट 2 और 3क ही प्रस्तुत किए हैं तथा इन ट्रेडरों के द्वारा कोई अन्य सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है। ई क्यू आर प्रस्तुत करना निर्यातकों की सुविधा के अनुसार चुनिंदा सूचना प्रस्तुत करके भरी जाने वाली केवल औपचारिकता नहीं है।
55. इसके अलावा, किसी भी उत्पादक ने परिशिष्ट-2 में भारत के लिए निर्यातों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की है। उत्पादकों से परिशिष्ट-2 में सूचना न होने की स्थिति में भारत के लिए फैक्टरी से बाहर निर्यात कीमत का पता लगाना संभव नहीं है।
56. पूर्वोक्त कारणों की दृष्टि से प्राधिकारी इन कंपनियों के प्रत्युत्तर को निरस्त करते हैं। तदनुसार, मै. जिनागसु रनझोंग हाई टेक क. लि., झांगीजियोगेंग शाजिंग स्टील कं. लि., झांगजीयागेंग होंगरिंग गाओक्सियन कं. लि., झांगजीयोगेंग, रोंगशेंग स्टील मेकिंग क. लि., झांगजीयागेंग होंगचांग गाओक्सियन कं. लि., और झांगजीयागेंग रनझोंग स्टील कं. लि. के लिए निर्यात कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।
- मै. सिनोमैटीरियल इंटरनेशनल कं. लि. मै. मानुचर स्टील हांगकांग लि., मै. बुरविल रिसोसिज लि. और अन्य ट्रेडरों के माध्यम से निर्यात करने वाली मै. जियांगसु योंगगेंग ग्रुप कं. लि. (उत्पादक) :**
57. उत्पादकों और निर्यातकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन मै. जियांगसु योंगगेंग ग्रुप कं. लि. के द्वारा किया गया था और असंबद्ध ट्रेडरों नामतः मै. सिनोमैटीरियल इंटरनेशनल कं. लि., मै. मानुचर स्टील हांगकांग लि., बुरविल रिसोसिज लि., स्मार्ट टाइमिंग स्टील लि., मैटल वन (शंघाई) कारपोरेशन, नावेक्स एशिया लि., वा ट्रेडिंग कं. लि., टेवू मैटल (हांगकांग) लि., टाटा इंटरनेशनल मैटल्स (एशिया) लि. और स्टीलफोर्स फॉर ईस्ट लि. के माध्यम से निर्यात किया गया था।
58. उपर्युक्त कंपनियों में से मैटल वन (शंघाई) कारपोरेशन, नावेक्स एशिया लि., वा ट्रेडिंग कं. लि., टेवू मैटल (हांगकांग) लि., टाटा इंटरनेशनल मैटल्स (एशिया) लि., और स्टीलफोर्स फॉर ईस्ट लि. ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अलावा, जियांगसु योंगगेंग ग्रुप कं. लि. के द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत के लिए निर्यातों की सूचना मै. स्मार्ट टाइमिंग स्टील लि. ने नहीं दी है। साथ ही, मै. बुरविल रिसोसिज लि. और सिनोमैटीरियल इंटरनेशनल कं. लि. के द्वारा सूचित भारत को निर्यातों की मात्रा जियांगसु योंगगेंग ग्रुप कं. लि. के द्वारा सूचित की गई मात्रा से मेल नहीं खा रही है।
59. अतः तथ्यों को छिपाने सहित पूर्वोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इन कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर को निरस्त करते हैं। तदनुसार, जियांगसु योंगगेंग ग्रुप कं. लि. के लिए निर्यात कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।
- जेनिथ स्टील ग्रुप कं. लि. (उत्पादक), जेनिसिज रिसोसिज कं. लि. (हांगकांग), स्मार्ट टाइमिंग स्टील लि. (हांगकांग निर्यातक), टॉपटिप होल्लिंग प्रा. लि. (निर्यातक)।**
60. उत्पादक, मै. जेनिथ स्टील ग्रुप कं. लि. द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादक ने जेनेसिस रिसोसिस कं. लि. (हांगकांग), टॉपटिप होल्लिंग प्रा. लि. (सिंगापुर) और विन फेथ ट्रेडिंग लि., चीन जन गण के माध्यम से भारत के लिए संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। विन फेथ ट्रेडिंग लि., चीन जन गण ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है। टॉपटिप होल्लिंग प्रा. लि. ने एक दूसरे ट्रेडर मै. कारगिल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. सिंगापुर के लिए संपूर्ण मात्रा को पुनः बिक्री कर दी है, जिसने कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। जेनेसिस रिसोसिस कं. लि. (हांगकांग) ने संबद्ध वस्तुएं स्मार्ट टाइमिंग स्टील लि. (हांगकांग) को बेच दी हैं जिसने फिर डी एच ए एम एम एस के ए स्विटजरलैंड के लिए संबद्ध वस्तुओं की पुनः बिक्री कर दी और वह भी प्राधिकारी को सहयोग करने में असमर्थ रहा।
61. अतः पूर्वोक्त ट्रेडरों/ निर्यातकों से असहयोग को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर को प्राधिकारी स्वीकृत नहीं करते हैं। तदनुसार, जेनिथ स्टील ग्रुप कं. लि. के लिए निर्यात कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।

माइनमैटल रिंगकोऊ मीडियम प्लेट कं. लि. (उत्पादक सह निर्यातक)

62. माइनमैटल रिंगकोऊ मीडियम प्लेट कं. लि. (एम वाई एम पी) द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एम वाई एम पी ने पी ओ आई के दौरान भारत के लिए सीधे ही संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।
63. भारतीय ग्राहकों की बिक्रियां सी एफ आर आधार पर होती हैं। एम वाई एम पी ने अंतर्देशीय माल-भाड़े, पत्तन प्रभारों, समुद्री माल-भाड़े और बैंक प्रभारों की वजह से समायोजनों के लिए दावा किया है और इनकी अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने रिफण्ड न करने योग्य वैट की वजह से और समायोजन किया है। तदनुसार, भारत औसत निर्यात कीमत का एम वाई एम पी के लिए फैक्टरी से बाहर स्तर पर निर्धारण किया है और इसको नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाया है।

जियानजिन क्रासिंगचेंग एलॉय मैटीरियल कं. लि. (उत्पादक) ने जियानजिन क्रासिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कं. लि. के माध्यम से निर्यात किया

64. उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जियानजिन क्रासिंगचेंग एलॉय मैटीरियल कं. लि. ("जे एक्स ए एम") के द्वारा संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया गया था और संबद्ध ट्रेडिंग कंपनी जियानजिन क्रासिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कं. लि. ("जे एक्स एस एस") के माध्यम से इनका निर्यात किया गया। प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करते समय प्राधिकारी ने जे एक्स ए एम के प्रत्युत्तर को इस वजह से अस्थायी तौर पर स्वीकार नहीं किया था कि जे एक्स ए एम ने परिशिष्ट-2 में भारत के लिए निर्यात से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की थी तथा परिशिष्ट-2 में ऐसी सूचना न होने पर भारत के लिए फैक्टरी से बाहर निर्यात कीमत का पता लगाना संभव नहीं था।
65. जे एक्स ए एम के द्वारा बाद में यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रारंभिक जांच परिणामों के जारी होने से पूर्व कंपनी ने परिशिष्ट-2 प्रस्तुत कर दिया है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है तथा यह पाया है कि जे एक्स ए एम ने नियम तारीख से काफी देर बाद परिशिष्ट-2 प्रस्तुत किया था। विलंब से प्रस्तुत करने के बावजूद प्राधिकारी ने जे एक्स ए एम और जे एक्स एस एस के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर की जांच की है क्योंकि जे एक्स ए एम ने भारत के लिए अपने निर्यातों के लिए ट्रेड जे एक्स एस एस द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट-2 के बारे में अपने प्रारंभिक निवेदन में हवाला दिया था। तथापि, जे एक्स ए एम और जे एक्स एस एस के प्रत्युत्तरों की विस्तृत जांच के बारे में प्राधिकारी ने निम्नानुसार नोट किया है :-
66. जे एक्स ए एम ने यह निवेदन किया है कि उसके उत्पादों का भारत और अन्य तीसरे देशों के लिए जे एक्स एस एस के माध्यम से निर्यात किया गया है। इसी प्रकार जे एक्स एस एस ने यह निवेदन किया है कि जे एक्स ए एम के द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं का भारत और अन्य तीसरे देशों के लिए निर्यात किया है। तथापि, अपने प्रत्युत्तर में जे एक्स ए एम के द्वारा सूचित निर्यात मात्रा जे एक्स एस एस के प्रत्युत्तर में उसके द्वारा सूचित की गई निर्यात मात्रा से मेल नहीं खाती है।
67. परिशिष्ट-4 में जे एक्स ए एम ने यह सूचित किया है कि उसने केवल तीसरे देशों के लिए ही संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है तथा उक्त परिशिष्ट में भारत के लिए किसी निर्यात के बारे में सूचना नहीं दी है। अतः उसके प्रत्युत्तर में जे एक्स ए एम के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के बीच आंतरिक गड़बड़ी है।
68. जे एक्स एस एस ने भी परिशिष्ट-7 और 9 में सूचना प्रस्तुत नहीं की है। परिशिष्ट-7 और 9 में पूरी सूचना न होने की स्थिति में प्राधिकारी के लिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि जे एक्स एस एस ने अपने एस जी ए व्ययों की वृसली कर ली है और भारत के लिए अपने निर्यातों पर उचित लाभ लिया है।
69. अतः उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए जे एक्स ए एम और जे एक्स एस एस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्युत्तर को प्राधिकारी स्वीकार नहीं करते हैं। तदनुसार, जे एक्स ए एम के लिए निर्यात कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है।

असहयोगी उत्पादक और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में चीन जन. गण. के अन्य किसी उत्पादक/ निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीन के सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर वायर रौड्स के लिए भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की है और इसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में दिखाया है।

पाटन मार्जिन

71. पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भारत के लिए निर्यात कीमत (निर्यातकों के द्वारा दावा की गई और प्राधिकारी के द्वारा स्वीकृत सभी समायोजन के निवल) की सामान्य मूल्य से तुलना की गई है। संबद्ध देश से सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए पी ओ आई के दौरान पाटन मार्जिन के बारे में नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में दिखाए अनुसार निर्धारण किया गया है :-

पाटन मार्जिन सारणी

क्र. सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य अमेरिकी डॉलर	निवल निर्यात मूल्य अमेरिकी डॉलर	पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर	पाटन मार्जिन %	डम्पिंग मार्जिन रेंज %
1.	चीन जन. गण.	माइनमैटल्स रिंग कोऊ मीडियम प्लेट कं. लि.	माइनमैटल्स रिंग कोऊ मीडियम प्लेट कं. लि.	***	***	***	***	50-60
2.	चीन जन. गण	अन्य	अन्य	***	***	***	***	90-100

72. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के सभी उत्पादकों निर्यातकों के द्वारा किए गए निर्यातों के संबद्ध में पाटन मार्जिन बहुत ही सार्थक हैं।

क्षति और कारणात्मक लिंकों का निर्धारण

73. अनुबंध-11 के साथ पठित पाटन रोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि “.....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए” क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग के लिए क्षति को दिखा सकते हैं। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में विचार करते हुए इसकी जांच करना जरूरी समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में काफी कमी हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी सीमा तक कीमतों को अन्यथा कम करना अथवा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है, जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी।

74. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति वाले सूचकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक लाभप्रदता, निवल बिक्रिया प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन, आदि के बारे में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 11 के अनुसार विचार किया गया है।

घरेलू उद्योग की क्षति के दावों के संबंध में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत

75. क्षति से संबंधित मुद्दों के बारे में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदन और प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक माने गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- क. घरेलू उद्योग क्षति, यदि कोई हो, जिन कारकों से होती हैं उनमें निर्यात निष्पादन, बढ़ी हुई ब्याज लागत, प्रति यूनिट बढ़ी हुई बिक्रियों की लागत आदि शामिल हैं। घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में घरेलू मांग के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई है। संबद्ध वस्तुओं की मांग वर्ष 2012-13 में 100 सूचकांक यूनिट से बढ़कर पी ओ आई (वार्षिक) में 160 प्वाइंट हुई। आयातों में बढ़ोतरी केवल मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए है।
- ख. जे. एस. डब्ल्यू का कर्नाटक संयंत्र पी ओ आई (क्यू 2) के दौरान बंद कर दिया था जिसके लिए याचिका में कुछ प्रकट नहीं किया गया है। कर्नाटक संयंत्र को बंद करने के लिए समायोजन करने के

बाद प्राधिकारी के द्वारा संशोधित क्षति सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में बढ़ोतरी की है और घरेलू उद्योग के उत्पादन के आधार वर्ष से काफी सुधार हुआ है। अतः इन कारकों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ है।

- ग. कथित आयातों की वजह से लाभप्रदता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। घरेलू उद्योग के लाभों में प्रति यूनिट ब्याज की लागत में वर्ष 2012-13 के 100 प्वाइंट से बढ़कर पी ओ आई में 177 प्वाइंट होने की वजह से गिरावट हुई है। तथापि, नकारात्मक कीमत में कमी यह दर्शाती है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू कीमतों को प्रभावित नहीं कर रही है।

घरेलू उद्योग के मत

76. घरेलू उद्योग के द्वारा क्षति संबंधी मुद्दों के बारे में निवेदन और प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दे निम्नलिखित हैं :-

- क. जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है। संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है।
- ख. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में उत्पादन के संदर्भ में तथा भारत में खपत के संदर्भ में भी पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी हुई है, यद्यपि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इसका कारण यह है कि आयातों ने मांग में बढ़ोतरी को बुरी तरह से जकड़ लिया है और संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में 2012-13 से पी ओ आई (क) में तेजी से बढ़ोतरी हुई।
- घ. घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी के अनुरूप उत्पादन और बिक्रियों में बढ़ोतरी नहीं कर सका है।
- ङ. घरेलू उद्योग की सामान सूचियों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद अपनी बिक्रियों को बढ़ा नहीं सका है। आयात भारत में मांग को बुरी तरह से जकड़ रहा है।
- च. भारत में कम कीमत वाले पाटित आयातों की वजह से कीमत में काफी कमी और नियंत्रण है।
- छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय अत्यधिक प्रभावित हुई है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय, निवल लाभों और नकद लाभों में नकारात्मक प्रवृत्ति हुई है और पी ओ आई के दौरान हानियां भी अत्यधिक हुई हैं।
- ज. घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन से उसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति किसी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। इसके अलावा, क्षति संबंधी मानदंडों की जांच करते समय याचिकाकर्ताओं ने निर्यातों से संबंधित सूचना की उपेक्षा की है और संपूर्ण क्षति विश्लेषण याचिकाकर्ताओं के घरेलू निष्पादन पर ही आधारित है।
- झ. विश्लेषण बहुत अधिक यह दर्शाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पादन के बढ़ते हुए पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में बढ़ोतरी और घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के बीच में सशक्त संबंध है।
- ञ. घरेलू उद्योग को आर्डर देते समय ग्राहक इस बात पर बल देते हैं कि घरेलू उद्योग की कीमत उसी महीने के दौरान विदेशी उत्पादक द्वारा दी गई कीमत से मिलनी चाहिए यद्यपि किसी विदेशी आपूर्तिकर्ता के द्वारा दिए गए प्रस्ताव की डिलीवरी 2 महीनों के बाद में ही होगी। कीमत में कटौती होने की उचित तुलना दो महीनों की विलंबित घरेलू बिक्रय प्राप्ति के बीच में होनी चाहिए। यदि प्राधिकारी इस समय विलंब को ध्यान में रखता है, तो कीमत में कमी होना नजर आएगा।
- ट. यह नोट करना भी प्रासंगिक होगा कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य में कच्चे माल की कीमतों में हुई गिरावट से काफी ज्यादा गिरावट आई है। इसके अलावा, यह नोट करना चाहिए कि आयात बहुत कम कीमतों पर आए हैं और घरेलू उद्योग को ऐसी कम कीमतों के अनुरूप होने के लिए बाध्य किया गया है कि उनकी कीमतें घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से नीचे चली गई हैं।
- ठ. हितबद्ध पक्षकारों ने यह निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की वजह स्वयं उनके आंतरिक कारकों जैसे अधिक निश्चित लागत भार और क्षमताओं का कम उपयोग करना है। ये दावे बहुत आम हैं और

समर्थन करने हेतु किन्हीं तथ्यों और आंकड़ों के बिना हैं। भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की वजह से क्षति हो रही है, इस तथ्य की पहले ही पुष्टि हो गई है। घरेलू उद्योग बहुत वर्षों से अस्तित्व में है और विगत में अच्छा कर रहा है।

प्राधिकारी द्वारा मुद्दों की जांच

77. क्षति और कारणात्मक लिंक के बारे में जांच की अवधि के बारे में घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों और प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक समझे गए निवेदनों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया है :-

- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य में पी ओ आई के दौरान काफी गिरावट आयी है और आयातों के कम हुए पहुंच मूल्य के बराबर लाने के लिए घरेलू उद्योग को पी ओ आई के दौरान अपने विक्रय मूल्यों को कम करना पड़ा था।
- ख. घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संपूर्ण क्षति विश्लेषण याचिकाकर्ताओं के घरेलू निष्पादन पर ही आधारित है।
- ग. प्राधिकारी ने इस आशय से हितबद्ध पक्षकारों के दावे का विश्लेषण किया गया है कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति अधिक निश्चित लागत भार और क्षमताओं का कम उपयोग करने सहित उनके स्वयं आंतरिक कारकों की वजह से है। भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की वजह से क्षति हो रही है, इस तथ्य की आगामी पैराग्राफों में पुष्टि कर ली गई है।

पाटित आयातों की मात्रा प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

मांग का आकलन

78. संबद्ध वस्तुओं की मांग का निर्धारण समान उत्पाद के भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्रयों को समस्त देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के साथ जोड़ कर किया गया है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त हुए आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है :-

विवरण (एम टी में)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 (ए)	पी ओ आई (जुलाई 2015 से दिसंबर 2015)	पी ओ आई (ए)
संबद्ध देश कुल पाटित आयात	1,60,582	1,16,366	7,70,493	8,27,721	4,95,732	9,91,463
अन्य देशों से आयात	2,03,688	71,595	1,00,927	1,06,142	53,835	1,07,670
कुल आयात	3,64,270	1,87,961	8,71,420	9,33,863	5,49,567	10,99,134
याचिकाकर्ताओं की घरेलू विक्री	11,55,858	12,26,631	10,83,019	15,03,914	7,82,421	15,64,842
समर्थकों की घरेलू विक्री	6,21,818	6,22,535	6,63,185	7,07,817	3,63,094	7,26,188
अन्य उत्पादकों की घरेलू विक्री	8,53,170	11,97,538	10,53,228	13,54,427	6,76,625	13,53,250
कुल मांग/ स्पष्ट खपत	29,95,116	32,34,665	36,70,853	45,00,022	23,71,707	47,43,414

आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

79. पाटित आयातों की मात्रा के बारे में प्राधिकारी के द्वारा यह विचार करना होता है कि क्या पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि पूर्णतः हुई है अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संदर्भ में हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा के बारे में निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :-

विवरण (एम टी में)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 (ए)	पी ओ आई (जुलाई 2015 से दिसंबर 2015)	पी ओ आई (ए)
संबद्ध देश से पाटित आयात	1,60,582	1,16,366	7,70,493	8,27,721	4,95,732	9,91,463
प्रवृत्ति	100	72	480	515	309	617
अन्य देशों से आयात	2,03,688	71,595	1,00,927	1,06,142	53,835	1,07,670
प्रवृत्ति	100	35	50	52	26	53
कुल आयात	3,64,270	1,87,961	8,71,420	9,33,863	5,49,567	10,99,134
प्रवृत्ति	100	52	239	256	151	302
कुल मांग/ स्पष्ट खपत	2,995,116	3,234,665	3,670,853	4,500,022	2,371,707	4,743,414
प्रवृत्ति	100	108	123	150	79	158
खपत के संदर्भ में संबद्ध देश से पाटित आयात	5%	4%	21%	18%	21%	21%
याचिकाकर्ताओं का उत्पादन	1,477,972	1,609,278	1,503,065	1,780,457	903,145	1,806,291
याचिकाकर्ताओं के कुल उत्पादन के संदर्भ में संबद्ध देश से पाटित आयात	11%	7%	51%	46%	55%	55%

80. उपर्युक्त सारणी में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :-

- क. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात अबाध रूप से वर्ष 2012-13 में 1,60,582 एम टी से बढ़कर पी ओ आई (क) में 9,91,463 एम टी हो गया।
- ख. याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के संदर्भ में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात वर्ष 2012-13 में 11 प्रतिशत से बढ़कर पी ओ आई (क) में 55 प्रतिशत हो गए।
- ग. भारत में खपत के संदर्भ में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का आयात वर्ष 2012-13 में 5 प्रतिशत से बढ़कर पी ओ आई (क) में 21 प्रतिशत हो गया है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत पर प्रभाव

81. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

82. यह जांच की गई कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में काफी कमी हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी सीमा तक कीमतों को अन्यथा कम करना अथवा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है, जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में कीमत में कटौती, कीमत पर दबाव और कीमत नियंत्रण के संदर्भ में जांच की गई है।

कम कीमत

83. क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं, इसका निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की है। इस संबंध में समान स्तर के ट्रेड के

बारे में उत्पाद के पहुंच मूल्य की सभी प्रकार की छूट और करों को निकाल कर घरेलू उद्योग के औसत विक्रय मूल्य के साथ तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण फैक्ट्री से बाहर के स्तर पर किया गया था। घरेलू कीमतों और पी ओ आई के दौरान कीमत कमी के मार्जिन को नीचे सारणी में दर्शाया गया है :-

विवरण	राशि (आई एन आर/ एम टी)
पहुंच मूल्य	28,093
घरेलू विक्रय मूल्य	***
कीमत में कटौती	***
पहुंच मूल्य के % के रूप में	***
कीमत में कटौती %	(5)-5

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत में कमी नकारात्मक है।

कीमत दबाव/ नियंत्रण

85. क्या पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से काफी हद तक कीमतें नियंत्रित हुई हैं, अथवा कीमतों में बढ़ोतरी रूकी है, जो काफी हद तक हुई होगी, इसका निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों के बारे में विचार किया। स्थिति नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गयी है :-

विवरण (रु./ प्रति एम टी)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015	पी ओ आई (जुलाई 2015 से दिसंबर 2015)
विनिर्माण और बिक्री की लागत	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	98	101	91	87
घरेलू विक्रय मूल्य	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	96	98	75	72
पहुंच मूल्य	38,582	37,816	34,310	28,816	28,093
प्रवृत्ति	100	98	89	75	73

86. यह नोट किया गया है कि घरेलू विक्रय मूल्य में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से अधिक है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के बराबर लाने के लिए घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री की कीमतों को कम किया है। अतः आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव और नियंत्रण हो रहा था।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

87. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 11 में यह अपेक्षा है कि क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणाम प्रभाव की एक वस्तुपरक जांच करना शामिल होगा। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभों, उत्पादन, बाजार शेयर, उत्पादकता, निवेशों पर लाभ, क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, सामान सूचियों, रोजगार, मजदूरियों, विकास, पूंजी निवेशों को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों को शामिल करते हुए उद्योग की स्थिति को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक

आर्थिक कारकों और सूचकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों के बारे में नीचे विचार किया है :-

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

88. उत्पादक, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के बारे में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था :-

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 (ए)	पी ओ आई (जुलाई 2015 से दिसंबर 2015)	पी ओ आई (ए)
प्रतिष्ठापित क्षमता (एम टी)	22,70,000	32,70,000	38,70,000	38,70,000	19,35,000	38,70,000
उत्पादन (पी यू सी)	14,77,972	16,09,278	15,03,065	17,80,457	9,03,145	18,06,291
उत्पादन (नॉन पी यू सी)	11,92,670	11,73,342	13,05,434	13,30,699	6,75,003	13,50,007
कुल उत्पादन	26,70,642	27,82,621	28,08,499	31,11,156	15,78,149	31,56,298
क्षमता उपयोग	118%	85%	73%	80%	82%	82%
घरेलू बिक्रियां (पी यू सी)	11,55,858	12,26,631	10,83,019	15,03,914	7,82,421	15,64,842

89. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि समान क्षमता का उपयोग करके बहुत उत्पादों का विनिर्माण किया जा सकता है। तदनुसार, कुल क्षमता और उत्पादन के आधार पर क्षमता उपयोग की गणना की गई है।

90. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट दर्शायी है। घरेलू उद्योग वर्ष 2012-13 के दौरान 118 प्रतिशत की सर्वोत्तम क्षमता उपयोग को प्राप्त कर सका है। तथापि, संबद्ध देश से पाटित आयातों में बढ़ोतरी होने के कारण पी ओ आई के दौरान यह गिरकर 82 प्रतिशत हो गया है।

लाभ, निवेश पर लाभ और नकद लाभ

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 (ए)	पी ओ आई (जुलाई 2015 से दिसंबर 2015)	पी ओ आई (ए)
कर पूर्ण लाभ (रु. करोड़ में) अर्थात् पी. बी. टी.	***	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	100	63	44	(211)	(112)	(224)
पी. बी. टी. (रु./ एम टी)	***	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	100	59	47	(162)	(165)	(165)
नकद लाभ (पी बी टी + मूल्यह्रास) (रु. करोड़)	***	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	100	73	57	(148)	(79)	(158)
नकद लाभ (रु./ एम टी)	***	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	100	69	61	(114)	(117)	(117)
आर ओ सी ई %	***	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	100	73	79	(54)	(60)	(60)

91. उपर्युक्त सारणी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि –

- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन की वजह से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर लाभ काफी प्रभावित हुआ है। उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 तक घरेलू उद्योग अच्छा लाभ अर्जित कर रहा था।
- ख. तथापि, पी ओ आई के दौरान संबद्ध देश से पाटन की वजह से घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर उचित लाभ अर्जित करने के बजाय बिक्रियों की लागत को वसूल नहीं कर सका है।

बाजार हिस्सा

92. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की नीचे दिए अनुसार जांच की गई है :-

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 (ए)	पी ओ आई (जुलाई 2015 से दिसंबर 2015)	पी ओ आई (ए)
मांग (एम टी)	2,995,116	3,234,665	3,670,853	4,500,022	2,371,707	4,743,414
सूचीबद्ध	100	108	123	150	79	158
बाजार हिस्सा						
याचिकाकर्ताओं का हिस्सा	39%	38%	30%	33%	33%	33%
समर्थकों का हिस्सा	21%	19%	18%	16%	15%	15%
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	28%	37%	29%	30%	29%	29%
संबद्ध देश का हिस्सा	5%	4%	21%	18%	21%	21%
अन्य देशों का हिस्सा	7%	2%	3%	2%	2%	2%

93. उपर्युक्त सारणी से प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी हुई है, यद्यपि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग भारत में बढ़ रही है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह यह है कि संबद्ध देश से आयातों ने मांग में बढ़ोतरी पर काफी मात्रा में कब्जा कर लिया है।

94. संबद्ध देश से आ रहे पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी के अनुरूप विचाराधीन उत्पादन की बिक्री बढ़ा नहीं सका है।

सामान सूची

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पी ओ आई (जुलाई 2015 से दिसंबर 2015)
औसत सामान सूची (एम टी)	63,650	62,871	77,271	118,979
प्रवृत्ति (सूचीबद्ध)	100	99	121	187

95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अधिक हो रही सामान सूचियों की स्थिति का सामना कर रहा है। आधार वर्ष की तुलना में सामान सूचियों के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। आयातों में बढ़ोतरी होने की वजह से घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हो गया है और बड़ी हुई मांग पर आयातों द्वारा कब्जा कर लिया है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

96. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादकता में अवनति से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। नीचे दी गई सारणी में यह देखा जा सकता है कि प्रति कर्मचारी की उत्पादकता 2012-13 में 100 सूचीबद्ध प्वाइंटों से बढ़कर पी ओ आई के दौरान 114 सूचीबद्ध प्वाइंट हो गई है।

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पी ओ आई
उत्पादकता	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	103	100	114

विकास

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	पी ओ आई (ए)
उत्पादन की लागत	%	-2%	3%	-14%
विक्रय मूल्य	%	-4%	2%	-27%
प्रति यूनिट लाभ/ हानि	%	-41%	-20%	-448%
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	-27%	9%	-176%

97. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षमता उपयोग, लाभों, निवेश पर लाभ, नकद लाभों के बारे में घरेलू उद्योग का विकास नकारात्मक रहा है।

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

98. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने संयंत्र और मशीनरी ने काफी निवेश किया है। तथापि, इन निवेशों के बावजूद, घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी कमी (विकृति) हो गई है और अतिरिक्त निवेश काफी तरह से प्रभावित हो सकता है।

पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

99. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आ रहे हैं और पाटन मार्जिन काफी है।

कारणात्मक संपर्क

100. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग की क्षति हुई है। घरेलू उद्योग के लिए पाटन और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच निम्नानुसार की गई है :-

तीसरे देश से आयात

101. संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से आयात पर्याप्त मात्रा में है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति अथवा खतरा हो सकता है।

मांग में कमी

102. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी है। तदनुसार, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति होने का कारण नहीं हो सकता है। वास्तव में, घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी के अनुरूप अपनी बिक्री और बाजार हिस्से में बढ़ोतरी नहीं कर सका है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों की और उनके बीच में व्यापार प्रतिबंध प्रथाएं

103. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार संबंधी ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके।

प्रौद्योगिकी में विकास

104. संबंधित उत्पाद के उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी में विकासों को घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारक माना जा सकता है।

खपत की पद्धति में परिवर्तन

105. घरेलू उद्योग इस किस्म की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिनका भारत में आयात किया गया है। खपत की पद्धति में संभावित बदलाव ऐसे कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने का दावा किया जा सके।

निर्यातिनिष्पादन

106. घरेलू उद्योग के लिए दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभव पर्याप्त विकृति से नहीं है। वास्तव में, घरेलू उद्योग के द्वारा निर्यातों में वस्तुतः गिरावट नहीं हुई है। किसी मामले में प्राधिकारी ने, जहां कहीं संभव हुआ, घरेलू निष्पादन के बारे में विचार किया है।

अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग के निष्पादन के बारे में प्राधिकारी के द्वारा किए गए आकलन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी के द्वारा विचार की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के बारे में है।

कारणात्मक संपर्क संबंधी तथ्य

108. पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को निम्नलिखित आधार पर पुष्टि की है :-

- जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है।
- संबद्ध वस्तुओं के आयातों में उत्पादन के संदर्भ में तथा भारत में खपत के संदर्भ में भी पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है।
- घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी हुई है, यद्यपि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इसका कारण यह है कि आयातों ने मांग में बढ़ोतरी को बुरी तरह से जकड़ लिया है।
- घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी के अनुरूप उत्पादन और बिक्रियों में बढ़ोतरी नहीं कर सका है।
- घरेलू उद्योग की सामान सूचियों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद अपनी बिक्रियों को बढ़ा नहीं सका है।
- भारत में कम कीमत वाले पाटित आयातों की वजह से कीमत में काफी कमी और नियंत्रण है।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय अत्यधिक प्रभावित हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग वर्ष 2014-15 तक अच्छे लाभ और नियोजित पूंजी पर आय अर्जित कर रहा था। तथापि पी ओ आई के दौरान लाभ और आय हानियों में बदल गए हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

109. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में उपरोक्त जांच से प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है। समस्त क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है। पाटित आयातों ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और इसे अत्यधिक माना गया है। संबद्ध देश से पाटित आयातों ने क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में अत्यधिक गिरावट आई है। प्राधिकारी का अन्तिम रूप से यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।

110. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों की संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से तुलना की है। संबद्ध देश में अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के बारे में भारत में पहुंच मूल्य का सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिनों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है।

क्षति मार्जिन

क्र. सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	एन आई पी अमेरिकी डॉलर	लैंडिड मूल्य अमेरिकी डॉलर	क्षति मार्जिन अमेरिकी डॉलर	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज %
1.	चीन गण राज	मिनमेटल्स यिंगकोउ मीडिम प्लेट कं. लि.	मिनमेटल्स यिंगकोउ मीडिम प्लेट कं. लि.	***	***	***	***	35-45
2.	चीन गण राज	अन्य सभी	अन्य सभी	***	***	***	***	50-60

111. यथा निर्धारित पाटन मार्जिनों और क्षति मार्जिनों का स्तर पर्याप्त है।

ज. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध

112. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उसमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे जांच के दौरान पहले भी उठा दिए गए हैं और उनका समुचित रूप से समाधान भी कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया गया है:

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

113. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध सारांश में नीचे दिए गए हैं:

- (क) घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि संदर्भ कीमत पर आधारित शुल्क से भारत में संबद्ध सामानों की आयात मात्रा पर पर्याप्त रोक नहीं लग पाई है। संबद्ध देश से आयात अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी काफी रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी जानकारी में आया है कि आयात कीमतें जांच की अवधि के बाद इनपुट लागत में काफी वृद्धि होने के बावजूद अनंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संदर्भ कीमत के आसपास ही रही हैं। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे घरेलू उद्योग को समुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतिम जांच परिणाम में निर्धारित शुल्क की सिफारिश करें। शुल्क के निर्धारित रूप को लागू करने से उपायों की प्रभावकारिता सुनिश्चित होगी क्योंकि इससे कीमत में हेराफेरी अथवा प्रवंचना की संभावना कम होगी।
- (ख) चीन जन गण से असहयोगी निर्यातकों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन से वायर रॉडों के संबंध में हाल के व्यापार उपचारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क की गणनात्मक दरें लगी हैं। भारतीयों को भी शुल्क लगाए जाने में समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

114. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध सारांश रूप में निम्नलिखित हैं:

- (क) जेएक्सएएम से जेएक्सएसएस में आपूर्ति में अंतर जेएक्सएसएस द्वारा रखे गए स्टॉक के कारण है। यह वह मामला नहीं है कि सामग्री सीधे ही जेएक्सएएम को भेजी जाती है। जेएक्सएसएस अपने स्टॉक का रख-रखाव करता है और इसीलिए अंतर है।
- (ख) जेएक्सएएम और जेएक्सएसएस ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और इसीलिए परिशिष्ट-7 और 9 में प्रावधान नहीं है। जेएक्सएएम के परिशिष्ट-4 में टंकण संबंधी त्रुटि है। निर्यात के तहत दर्शाई गई सभी बिक्रियां भारत सहित निर्यात बाजार में बिक्रियों के लिए जेएक्सएसएस को की गई बिक्रियां हैं, यद्यपि यदि उसे "दूसरे देशों को किए गए निर्यात" के रूप में उल्लिखित किया गया है।
- (ग) बीबीजी और बीबीआईई ने प्राधिकारी से कोई ब्यौरे नहीं छिपाए हैं। बीबीजी और बीबीआईई के बीच एक एजेंसी करार है जिससे बीबीआईई को बीजक बढ़ाने की अनुमति मिलती है और बीबीजी की ओर से क्रेताओं के साथ संविदाएं करने की अनुमति होती है तथा बीबीआईई द्वारा प्राप्त राशि खर्चों को घटाने के बाद बीबीजी को अंतरित की जाती है।
- (घ) मैसर्स निंगबो सीआईएमईआई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ने पहले ही अपना उत्तर दे दिया है। अतः प्रकटन विवरण में यह टिप्पणी कि हमने रिकार्ड में पूरी सूचना नहीं दी है, मामले के तथ्यों में बनती नहीं है।
- (ङ) मनुचर स्टील हांगकांग लि. द्वारा भारत को किए गए निर्यातों की सूचना न दिए जाने के संबंध में यह अनुरोध है कि बीबीजी ने उसके पास उपलब्ध सभी ब्यौरे दिए हैं और वे दूसरों के द्वारा प्रस्तुत सूचना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम प्राधिकारी का ध्यान जापान (डब्ल्यूटी/डीएस184/एबीआर) से कुछ हॉट रोलड उत्पादों पर अमेरिकी-पाटनरोधी उपाय में डब्ल्यूटीओ अपील निकाय की रिपोर्ट दिनांक 24 जुलाई, 2001 की ओर आकर्षित करना चाहेंगे जिसमें यह माना गया था कि जांचकर्ता प्राधिकारी उस सूचना के संबंध में निर्यातकों पर अनुपयुक्त भार नहीं डाल सकता अथवा पूरे मानक के संबंध में जोर नहीं डाल सकता जो उनके नियंत्रण में नहीं है।

- (च) एनईआईएल ने दोबारा दोहराया है कि सेल एसआई 52100 ग्रेड के विशेष ऑर्डर की सुपुर्दगी करने में विफल रहा था और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एसआई 52100 तथा एसआई 8720 को हटाए जाने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, एनईआईएल ने पाटन एवं क्षति मार्जिन का पीसीएन-वार निर्धारण किए जाने का अनुरोध किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

115. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति हैं और उन्हें पहले ही प्रकटन विवरण में हल कर दिया गया है। उपर्युक्त जांच परिणाम यथा तथ्यतः पक्षकारों के इन तर्कों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में उस सीमा तक जांच की है जहां तक वे संगत हैं और अन्यत्र जिनका समाधान नहीं किया गया है:
- (क) जेएक्सएम और जेएक्सएसएस द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में कि मात्रा में अंतर जेएक्सएसएस द्वारा रखे गए स्टॉक के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में उत्पादक/निर्यातक द्वारा रिकार्ड में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि परिशिष्ट-7 और 9 को इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना व्यापारी और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है कि एमईटी में इसका दावा किया है अथवा नहीं। परिशिष्ट-7 और 9 का प्रयोजन इस बात की जांच करना है कि क्या व्यापारी/निर्यातक ने अपने एसजीए खर्च वसूल कर लिए हैं और उपयुक्त लाभ मार्जिन लिया है अथवा नहीं। अतः जेएक्सएम और जेएक्सएसएस को विशेष आधार प्रदान करना संभव नहीं है।
- (ख) बीबीजी और बीबीआई ने प्राधिकारी के समक्ष कोई नए तथ्य नहीं रखे हैं और मुद्दे को स्पष्ट करने में असफल रहा है कि यदि बीबीआई एक निर्यातक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है तो बीबीआई भारत में ग्राहकों के साथ संविदाएं कैसे करता है और अपने नाम पर बीजक कैसे जारी करता है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स निंगबो सीआईएमआई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. ने बहुत देर से उत्तर प्रस्तुत किया है जो कि प्राथमिक जांच परिणामों के काफी बाद की है। इसके अतिरिक्त, कुछ व्यापारियों ने सूचना दबाई है। अतः प्राधिकारी बीबीजी और बीबीआई को अलग से आधार प्रदान करने में असमर्थ हैं।
- (ग) जहां तक क्षति रहित कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग की चिंताओं का संबंध है, प्राधिकारी यह देखते हैं कि क्षति रहित कीमत का परिकलन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है।
- (घ) संदर्भ कीमत की बजाए निर्धारित शुल्क के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबद्ध सामानों के लिए संदर्भ कीमत आधारित शुल्क का रूप उपयुक्त है और ऐसे कोई विवशकारी कारण नहीं हैं कि प्राथमिक जांच परिणाम में सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप से हटा जाए।
- (ङ) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एसआई 52100 और एसआई 8720 को हटाने के लिए एनईआईएल द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग एसआई 52100 और एसआई 8720 के समतुल्य ग्रेडों का विनिर्माण कर रहा है और इसीलिए एनईआईएल के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

झ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

116. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा और इसीलिए ग्राहकों को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
117. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग करते हुए विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संबंधित प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित शुल्क लगाने से ग्राहक के लिए महत्वहीन लागत प्रभाव होंगे। अतः भारतीय बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाए। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों से उत्पन्न अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की बढ़ोत्तरी रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्पों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सिफारिशें

118. हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:
- (क) संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम है।
- (ख) घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध आयात के निमित्त वास्तविक क्षति हुई है।
- (ग) यह क्षति संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण हुई है।
119. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी। पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं उनके कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।
120. कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, इनमें से जो भी कम हो, लगाने की सिफारिश निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के बराबर करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्ति की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 8 में दर्शाई गई राशि तथा संबद्ध सामानों के बीच अंतर के रूप में लगाने की सिफारिश करते हैं। बशर्ते कि पहुँच मूल्य कॉलम 8 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो। इस प्रयोजन के लिए आयात का पहुँच मूल्य सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर पर होगा। यदि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है तो सिफारिश किए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की वैधता केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 02.11.2016 की अधिसूचना संख्या 51/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होगी।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	यूनिट	करेंसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113.	7213 और 7227	बार्स और रॉड्स, गैर-अलॉय स्टील अथवा अलॉय स्टील अथवा आयरन के अनियमित रूप से हॉट रोलड कॉइल, जिनमें (i) प्रशुल्क मद 72131090 (सामान्य रूप से रिबार अथवा टीएमटी बार के रूप में ज्ञात) के तहत आने वाली रॉबिन प्रक्रिया के दौरान उत्पादित इंडेंटेशन, रिक्स, ग्रूक्स अथवा अन्य विकृतियां, (ii) प्रशुल्क शीट्स 7221 के तहत आने वाली स्टेनलेस स्टील के बार तथा रॉड और (iii) प्रशुल्क शीट्स 72271000 के तहत आने वाली उच्च गति की स्पीड की बार एवं रॉड शामिल नहीं हैं।	चीन जन गण	चीन जन गण	मिनमेटल्स यिंगकोउ प्लेट कं. लि.	मिनमेटल्स यिंगकोउ प्लेट कं. लि.	535	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
114.	- वही -	- वही -	चीन जन गण	चीन जन गण	क्रम संख्या 1 के अलावा अन्य संयोजन		546	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
115.	- वही -	- वही -	चीन जन गण	चीन जन को छोड़कर कोई अन्य भी देश	कोई अन्य	कोई अन्य	546	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

116.	- वही -	- वही -	चीन जन गण को छोड़कर कोई अन्य भी देश	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	546	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
------	---------	---------	--	--------------	----------	----------	-----	--------	-----------------

121. केन्द्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के बाद इस अंतिम जांच परिणाम के विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जाएंगी।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2017

FINAL FINDINGS

Sub : Anti-dumping investigation concerning imports of “Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel” originating in or exported from China PR-reg.

F. No. 14/17/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules) thereof M/s Steel Authority of India Limited, M/s Rashtriya Ispat Nigam Limited, M/s Usha Martin Limited and M/s JSW Steel Limited (hereinafter also referred to as petitioner companies or the applicants) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the AD Rules, for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “**Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel**” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR-reg. (hereinafter also referred to as the subject country), and requested for initiation of an investigation for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

- The Authority on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant issued a public notice dated 02nd June 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in accordance with Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
- The Authority vide Preliminary Findings issued vide Notification No.14/17/2016-DGAD dated 27.09.2016 recommended provisional anti-dumping duty in the present investigation. Ministry of Finance issued a customs notification imposing provisional anti-dumping duty vide Customs Notification No. 51/2016-Customs (ADD) dated 02.11.2016 accepting the recommendations of the Authority.

A. Procedure

- The procedure described below has been followed:
 - The Authority notified the embassy of subject country in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.
 - The Authority sent copy of initiation notification to the embassy of subject country in India, known producers/ exporters from the subject country and known importers/ users/ associations of the subject goods as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.

- c. The Authority forwarded copy of the non-confidential version of the application to embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country and known importers of the subject goods, in accordance with the AD Rules. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- d. The embassy of subject country in India were also requested to advise the producers/exporters from their country to file their responses within the prescribed time limits.
- e. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - 1. Jiuquan Iron & Steel (Group) Co. Ltd.
 - 2. Handan Iron & Steel Group Co. Ltd.
 - 3. Lianyuan Iron & Steel Group Co. Ltd.
 - 4. Baosteel Group Corp
 - 5. Wuhan Iron & Steel (Group) Corp.
 - 6. Benxi Iron & Steel (Group) Special Steel Co Ltd.
 - 7. Lingyuan Iron & Steel (Group) Co. Ltd.
 - 8. Shougang Changzhi Iron & Steel Ltd.
 - 9. Hangzhou Iron & Steel Group Company
 - 10. Anfeng Steel Structure Materials Co. Ltd.
 - 11. Tianjin Xuboyuan Iron & Steel Trading Co. Ltd.
- f. In response to the initiation notification, the following producers and exporters/traders from the subject country have filed response to exporter's questionnaire:
 - 1. Jiangsu Shagang Material Trade Co. Ltd. (Exporter)
 - 2. B&L Metal (HK) Limited (Exporter)
 - 3. Jinagsu Runzhong High Tech Co. Ltd (Producer)
 - 4. Zhangjiagang Shajing Steel Co. Ltd. (Producer)
 - 5. Zhangjiagang Hongxing Gaoxian Co. Ltd (Producer)
 - 6. Zhangjiagang Rongsheng Steel Making Co. Ltd. (Producer)
 - 7. Jinagsu Shagang International Trade Co. Ltd. (Exporter)
 - 8. B&L International Investment Co. Ltd. (Exporter)
 - 9. Zhangjiagang Hongchang Gaoxian Co. Ltd.(Producer)
 - 10. Zhangjiagang Runzhong Steel Co. Ltd. (Producer)
 - 11. Xinsha International Pte. Ltd. (Exporter)
 - 12. Minmetals Yingkou Medium Plate Co. Ltd. (Producer)
 - 13. Sinomaterial International Co. Ltd. (Exporter)
 - 14. Manuchar Steel Hong Kong Limited Exporter)
 - 15. Burwill Resources Limited (Exporter)
 - 16. Jiangsu Yonggang Group Co. Ltd. (Producer)
 - 17. Genesis Resources Co. Ltd (Hong Kong)
 - 18. Smart Timing Steel Limited (Exporter)
 - 19. Toptip Holding Pte. Ltd. (Exporter)

20. Zenith Steel Group Co. Ltd. (Producer)
 21. Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co. Limited (Exporter)
 22. Unisteel International DMCC (Exporter)
 23. Win Faith Trading Limited (Exporter)
 24. Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited (Exporter)
 25. Benxi Beiyong Iron and Steel Group Imp. And Exp. Corp. Ltd. (Exporter)
 26. Benxi Beitai Gaosu steel Wire Rod Co. Ltd. (Producer)
 27. Future Materials Industry (Hong Kong) Co. Limited (Exporter)
 28. Jiangyin Xingcheng Alloy Material Co., Ltd (Producer)
 29. Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd (Exporter)
- g. Further, the following exporters/traders have filed only Appendix-2 and 3A instead of filing the complete questionnaire response.
1. Hong Kong Grand International Co. Ltd.
 2. Hyosung Corporation
 3. Steelco Pacific Trading Limited
 4. Steelforce Far East Ltd.
 5. Tata International Metals (Asia) Limited
 6. Unisteel International DMCC (Seperately filed)
- h. None of the producers/exporters from China PR has claimed Market Economy Treatment (MET) rebutting the non-market economy treatment in the present investigation.
- i. Questionnaires were sent to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
1. A.A. International
 2. Aggarwal Impex
 3. D.P. Wires Pvt. Ltd.
 4. Garg Inox Ltd.
 5. H.D. Wires Pvt. Ltd.
 6. Indian Wire & Steel Products
 7. J.S. Industries Pvt. Ltd.
 8. Kadimi Special Steels Pvt. Ltd.
 9. Lakshmi Card Clothing Mfg. Co. Pvt. Ltd.
 10. Makalu Trading Ltd.
 11. Nirmal Wires Pvt. Ltd.
 12. Oceanic Overseas
 13. Pankaj Steel Corporation
 14. R.K. Steels
 15. Sterling Tools Ltd.
 16. Transnational
 17. Uday Industries

18. V.N.C. Electrodes
 19. Vidhi Impex
 20. Weldwell Electrodes
 21. Yatin Steels India Pvt. Ltd.
 22. Zarhak Steels Ltd.
- j. The following importers/users of the subject goods have responded in the form of questionnaire responses:
1. Apar Industries Limited
 2. Rajratan Global Wire Ltd.
 3. National Engineering Industries Limited (NEIL)
 4. Indian Wire & Steel Products
 5. FAG Bearings India Limited
- k. During the investigation following parties have filed submissions/comments:
1. China Chamber of International Commerce, (“CCOIC”)
 2. Jiangsu Yonggang Group Co. Limited
 3. Sinomaterial International Co. Limited
 4. Manuchar Steel Hong Kong Limited
 5. Burwill Resources Limited
 6. Zenith Steel Group Co. Limited
 7. Smart Timing Steel Limited
 8. Toptip Holding Pte. Limited
 9. Minmetals Yingkou Medium Plate Co. Ltd
 10. Benxi Beitai Gaosu Steel Wire Rod Co., Limited
 11. Benxi Beiyong Iron and Steel Group Imp. and Exp. Corp. Ltd.
 12. Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited
 13. Future Materials Industry (Hong Kong) Co.
 14. Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co., Limited
 15. Unisteel International DMCC
 16. Win Faith Trading Limited
 17. Ningbo CIMEI Import & Export Co. Limited
 18. National Engineering Industries Limited (NEIL)
 19. Ball & Roller Bearing Manufacturers Association of India
 20. Steel Wire Manufacturers Association of India (SWMAI)
 21. Jiangyin Xincheng Alloy Material Co. Ltd. and Jiangyin Xincheng Special Steel Works Co. Ltd.
 22. FAG Bearings India Limited
 23. Jiangsu Shaganag International Trade Co. Limited

- l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in the present discourse statement.
- m. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- n. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.
- o. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- p. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules. It has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- q. Considering the fact that the subject goods are being imported in various grades/sizes/dimensions, the applicants had proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to PCN comparison for computing the dumping margin and injury margin. However, keeping in mind the factual matrix of the case, the Authority has not adopted PCN to PCN comparison.
- r. Verification of the information provided by the applicant domestic industry was carried out by the Authority to the extent deemed necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- s. Investigation was carried out for the period starting from 1st July 2015 to 31st December 2015 (6 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2012-13, 2013-14, 2014-15, April 2015 to December 2015 and the POI.
- t. The petitioners had submitted the petition alleging dumping of the subject goods from the subject country relying upon transaction wise imports data sourced from IBIS. However, request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation. The Authority has relied upon the transaction-wise DGCI&S import data.
- u. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 04th May, 2017. All the parties attending the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally by 09th May, 2017. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to submit their rejoinders by 15th May, 2017.
- v. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- w. Exchange rate for conversion of US\$ to INR is considered for the POI as INR 65.93 as per customs data.
- x. In this notification, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

- y. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 12.08.2017. The post Disclosure Statement submissions received from the domestic industry and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

B. Product under Consideration and Like Article

5. The product under consideration (PUC) in the present investigation is:

The product under consideration in the present investigation is bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel or alloy steel (commonly known as “Wire Rods”).

These products are of prime and non-prime category and are in all sizes. These products conform to various qualities of steels including but not limited to electrode, free cutting, forging, cold heading, low / medium / high carbon steels, drawing, ball bearing steel, case hardening steel, spring steel, corrosion resistant steel, weathering steel, structural steel and many more qualities of steel. However, following products, are not included in the scope of the product under consideration:

- a. *Bars and rods containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process falling under Tariff Item 72131090 (commonly known as rebars or TMT bars).*
 - b. *Bars and rods of Stainless steel falling under Tariff Heading 7221.*
 - c. *Bars and rods of High speed steel falling under Tariff Item 72271000*
6. The PUC is used in many applications and sectors such as automotive components, welding electrodes, fasteners including nuts and bolts, nails, railway sleepers, general engineering, binding wires for construction industry, armoured cables etc.
7. The PUC is classified under Custom Tariff Heading 7213 and 7227. The Customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

B.1 Views of the Interested Parties

8. Submissions made by exporters, importers, users and other interested parties with regard to issues related to PUC and considered relevant by the Authority are, inter alia, as follows:
- a. There is no ‘like article’ being produced by the applicants. Domestic Industry (DI) is not able to meet some of the quality parameters required to be covered for producing high quality “Bearings”. Although the domestic steel producers are able to produce steel with oxygen level > 10 PPM, they are not capable of fulfilling requirements where oxygen level to be maintained in steel is less than 6-8 PPM.
 - b. Certain high end grades of wire rods should be excluded from the product scope as below:
 - i. Wire rods of SAE 52100 grades - used for manufacturing of bearing needle wire
 - ii. High end spring steel wire rods for manufacturing of critical spring wires used in automobile industries
 - iii. High end tyre cord wire rods used for manufacturing of tyre cords used in aAuto tyre industries
 - iv. Higher carbon range (0.85 and above) wire rods used for manufacturing of wires like, spring steel wire, PC wire, ACSR core wire, etc.
 - c. High carbon grade steel should be excluded from the product scope for the reason that there is a demand-supply gap.
 - d. There is only one manufacturer of ‘bearing grade wires/wire rods’ in India, namely, Mukand Limited. Even Mukand Ltd. is not able to fulfill the product requirements. Moreover, Mukand Limited is also not an interested party requesting imposition of anti-dumping duty. HS Codes 72283019, 72283029, 72299090, 72279030, 72279040 and 72279090 should be excluded from the purview of the investigation. “Bearing Grade” should be kept outside the scope of the subject investigation and duty

should not be recommended on the imports of “bearing grade bars and wire rods” falling under Indian HS Classification 7227, 72279030, 72279040 and 72279090.

- e. SAE52100 and SAE8720 grade wire rods falling under tariff items 7227 9040 and 7227 9090 should be excluded from the product scope as the domestic industry is not manufacturing like articles possessing the specification of SAE52100 and SAE8720.
- f. Further, NEIL has alleged that the Steel Authority of India Limited (“SAIL”) had failed to deliver a particular order of SAE52100 grade and has submitted confidential evidence of the delivery failure and the Minutes of Meeting between NEIL and SAIL officials.
- g. The Domestic Industry has failed to provide documentary evidence substantiating the production of “bearing grade bars and wire rods” falling under Indian HS Classification 7227, 72279030, 72279040 and 72279090.
- h. It is submitted that the manufacturing process of wire rods of Tariff Heading 7213/7214 and bars of Tariff Heading 7227/7228 are different and requires different set of machineries. Thus, 7214 and 7228 are not like articles and, therefore, beyond the subject matter of this investigation.
- i. The PUC defined is extremely vague, wide and amorphous. It includes all sizes of wire rods including those which are not manufactured by the DI. As per the product brochure JSW is capable of manufacturing wire rods other than bearing steel of size up to 22 mm diameter. RINL is not capable of manufacturing wire rods of sizes more than 14 mm. Scope of PUC must be limited for size up to 14 mm diameter and not all sizes.
- j. 100 Cr6 grade alloy steel bars which is equivalent to SAE 52100 grade is not produced by the applicants and cannot be included in the product scope.

B.2 Views of the domestic industry

9. The submissions made by the domestic industry (DI) and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. DI has the capability to manufacture and are manufacturing high end spring wire steel wire rods, high end tyre cord wire rods used in the automobile industry and grades equivalent to SAE 52100. Therefore, the claim of the interested parties for exclusion of these grades is unwarranted.
 - b. With regards to allegation of NEIL that that the Steel Authority of India Limited (“SAIL”) had failed to deliver a particular order of SAE52100 grade, the DI has submitted that NEIL has failed to provide the non-confidential version of the evidence. In absence of non confidential version of the evidence, the DI will not be able to provide its comments on the same. Further, without accepting the allegations of NEIL, domestic industry submits that one independent incident of non-delivery by one of the constituents of the domestic industry cannot be a ground for a particular grade to be excluded from the product scope.
 - c. Presence of a demand-supply gap for “High carbon grade steel” cannot be a ground for excluding it from the product scope. The fact that the particular product is being dumped into India and the same is causing injury to the domestic industry is a ground for imposition of duties. Further, interested parties should explicitly mention the type of high carbon wire rod that it is seeking to get excluded from the product scope. In the absence of the specific grade, no detailed submission can be filed rebutting this issue.
 - d. DI has the capability to manufacture and are manufacturing wire rods of ball bearing quality falling under tariff item 7227 9030 and wire rods of cold heading quality falling under tariff item 7227 9040. Therefore, the claim of the interested parties for exclusion of these grades is unwarranted.
 - e. The present application relates to wire rods in coil form falling under tariff heading 7213 and 7227 of the customs tariff. The present application does not cover bars and rods in straight length falling tariff heading 7214 and 7228. Therefore, the claim of the interested parties for exclusion of bar and rods falling under tariff heading 7214 and 7228 does not make any sense.
 - f. The claim of the interested parties for exclusion of wire rods falling under tariff item 7227 9090 cannot be entertained unless the interested parties specify the exact grade for which exclusion is required.

Tariff item 7227 9090 is residual heading (“Others”) and covers a broad range of products within its ambit.

- g. The claim of the interested parties for exclusion of products falling under tariff item 7229 9090 does not make any sense because tariff heading 7229 pertains to “wire of other alloy steel”. The present application relates to wire rods and not wire.
- h. The claim of interested parties for restricting the scope of PUC upto 14mm diameter cannot be entertained because the domestic industry has the capability to manufacture the subject goods of more than 14mm diameter as and when orders are placed on them. In fact, the interested parties have failed to demonstrate that they require PUC of more than 14mm diameter and that they have placed orders of higher diameter with DI but the DI has failed to supply the same. In the absence of such information from the interested parties there is no basis of restricting the scope of PUC upto 14mm diameter.
- i. DI has the capability to manufacture and are manufacturing wire rods with oxygen level less than 6-8 PPM.
- j. DI has the capability to manufacture and are manufacturing wire rods of 100 Cr6 grade alloy steel.

B.3 Examination of the Authority

- 10. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the PUC related issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed hereunder.
- 11. With regard to the contention of the interested parties for exclusion of certain products from the scope of the PUC, the Authority is unable to accept the claims of the interested parties due to following reasons:
 - i. DI is manufacturing high end spring wire steel wire rods, high end tyre cord wire rods used in the automobile industry, higher carbon range (0.85 and above) wire rods used for manufacturing of wires like, spring steel wire, PC wire, ACSR core wire etc. and also grades equivalent to SAE 52100 and SAE8720.
 - ii. DI is manufacturing wire rods of ball bearing quality falling under tariff item 7227 9030 and wire rods of cold heading quality falling under tariff item 7227 9040.
 - iii. The present application relates to wire rods in coil form falling under tariff heading 7213 and 7227 of the customs tariff. The present application does not cover bars and rods in straight length falling tariff heading 7214 and 7228.
 - iv. Tariff item 7227 9090 is residual heading (“Others”) and covers a broad range of products within its ambit. The claim of the interested parties for exclusion of wire rods falling under tariff item 7227 9090 cannot be entertained unless the interested parties specify the exact grade for which exclusion is required.
 - v. The claim of the interested parties for exclusion of products falling under tariff item 7229 9090 is irrelevant. Tariff heading 7229 pertains to “wire of other alloy steel”. Current investigation only covers wire rods and not wire.
 - vi. The claim of interested parties for restricting the scope of PUC upto 14mm diameter cannot be entertained because the domestic industry has the capability to manufacture the subject goods of more than 14mm diameter. The interested parties have failed to demonstrate that they have placed orders of higher diameter with DI and DI has failed to supply the same.
 - vii. DI is manufacturing wire rods with oxygen level less than 6-8 PPM.
 - viii. DI is manufacturing wire rods of 100 Cr6 grade alloy steel.
- 12. As regards the contention that the PUC is too broad and vague, the Authority notes that the PUC has been appropriately defined keeping in view the imports from the subject country and production and supply position of the domestic industry. The Authority has thoroughly examined the contentions by all parties before arriving at the product scope.
- 13. With regard to like article, Rule 2(d) of the AD Rules provides as follows: -"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in

India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation. On the basis of information on record and considering the submissions made by the interested parties, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers use the two interchangeably. The Authority holds that the products manufactured by the applicants constitute like article to the subject goods being imported into India from the subject country.

14. The product under consideration (PUC) in the present investigation is confirmed as under:

The product under consideration in the present investigation is bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel or alloy steel (commonly known as “Wire Rods”).

These products are of prime and non-prime category and are in all sizes. These products conform to various qualities of steels including but not limited to electrode, free cutting, forging, cold heading, low / medium / high carbon steels, drawing, ball bearing steel, case hardening steel, spring steel, corrosion resistant steel, weathering steel, structural steel and many more qualities of steel. However, following products, are not included in the scope of the product under consideration:

- a. *Bars and rods containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process falling under Tariff Item 72131090 (commonly known as rebars or TMT bars).*
- b. *Bars and rods of Stainless steel falling under Tariff Heading 7221.*
- c. *Bars and rods of High speed steel falling under Tariff Item 72271000*

15. The PUC is used in many applications and sectors such as automotive components, welding electrodes, fasteners including nuts and bolts, nails, railway sleepers, general engineering, binding wires for construction industry, armoured cables etc.

16. The PUC is classified under Custom Tariff Heading 7213 and 7227. The Customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

C. Confidentiality

C.1 Views of Exporter, importers and other Interested Parties regarding the standing of domestic industry

17. Following are the issues raised by interested parties with respect to excessive confidentiality:

- a. Copy of Original/Raw transaction-wise import data obtained from IBIS has not been provided in excel file format.
- b. The company-wise production and sales volume detail of the domestic producer other than the applicant has not been provided.
- c. The item wise details of constructed value as well as normal value have been kept confidential and even ranges of normal value have not been given.
- d. The domestic industry has not provided any evidence with regard to the adjustments claimed by them for ocean freight, marine insurance, inland freight, handling charges and VAT adjustment while deriving ex-factory export price.
- e. It is submitted that the domestic industry resorted to excessive confidentiality depriving the interested parties from offering meaningful comments which is completely against the confidentiality provisions provided in the AD Rules.
- f. The applicant industry has kept considerable information confidential without providing any justifiable reasons like selling price, cost of production, ROCE, productivity, employment, calculation of working capital, interest on term loan, depreciation, miscellaneous income, purchase and sales policy, inventory valuation, quality control procedure etc. This is not permissible under the Rules as can be seen from the provisions above.

- g. Anti-Dumping authority has stated that they have relied on DGCIS data but a copy of DGCIS data has not been enclosed with preliminary findings.
- h. The Authority has accepted the confidentiality claim of the DI over JPC data. However, the Authority failed to notice that JPC data is available in public domain.

C.2 Views of the Domestic Industry

18. Few interested parties are of the view that the domestic industry has exercised excessive confidentiality in the petition by keeping confidential - i) IBIS import data; ii) company-wise production and sales volume details; iii) item-wise details of constructed normal value; iv) evidence regarding adjustments for ocean freight, marine insurance, port expenses, etc.; v) domestic selling prices; vi) profit and ROCE in %age terms; viii) Constructed Normal value etc. The domestic industry wholly denies and objects to the above contentions. First of all, it is clarified that Rule 7 of the AD Rules allows a party to claim confidentiality on information. Rule 7 also mandates that confidential information should be provided in non-confidential summary to interested parties, and where that is not possible, reasons should be provided why summarization is not possible. The domestic industry has claimed confidentiality on certain data in compliance with Rule 7 of the AD Rules. The Designated Authority has also accepted the domestic industry's confidentiality claims. Therefore, the above contentions by interested parties hold no water. Further, import data for this investigation is already placed in the public file. Therefore, contentions regarding non availability of import data are unfounded.
19. Further, domestic industry has not claimed confidentiality on the JPC data used in the Petition. The domestic industry has relied on JPC data for the purpose of determining the total domestic production volumes of the like product. The absolute JPC data figures that have been used has been provided in the Petition and the same is not even indexed.

C.3 Examination by the Authority

20. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule(2),(3)(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality are examined and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

D. Domestic Industry and Standing

22. Rule 2 (b) of the AD rules defines the domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

23. The application in the present case has been filed by M/s Steel Authority of India Limited, M/s Rashtriya Ispat Nigam Limited, M/s Usha Martin Limited and M/s JSW Steel Limited. The production of the aforesaid producers accounts for a major proportion of the total domestic production in India. The application has also been supported by two other domestic producers, namely, Tata Steel Limited and Jindal Steel and Power Limited.

D.1 Views of Exporter, importers and other Interested Parties regarding standing of the domestic industry.

24. The Applicant producers constitute mere 40% of the total domestic production and do not satisfy Rule 2(b) of the AD Rules. The Authority must elicit information in relation to production of other producers from the Central Excise Commissionerate. A 40% share of the total production can in no way confer to the requirement of Rule 2(b). Injury Examination based on 40% domestic production would give a skewed picture of injury and Authority should consider calling for more producers to make the share at least 50%.
25. Two supporters, namely, Tata Steel Ltd and Jindal Steel and Power Ltd have supported the application but no disclosure has been made regarding the information relating to imports of the PUC by the aforesaid supporters. The support letters were given prior to filing of the application. Rule 5(3) makes it apparent that any support to the application can be made only after filing of the said application before DGAD.
26. Usha Martin Limited cannot be included in the scope of the ‘domestic industry’ as Usha Martin is one of the importer of subject goods at Page 93 of the Application.

D.2. Views of the Domestic Industry

27. The following are the submissions of the domestic industry with respect to the issues raised by various interested parties regarding standing of the domestic industry:
- M/s. Usha Martin has not imported the subject goods during POI as is evident from the certificate provided by M/s Usha Martin Limited along with the application filed with the Authority.
 - The mentioning of name of M/s Usha Martin Limited on page 93 of the application under the list of known importers is merely a clerical mistake.
 - There is no provision under the AD Rules which mandates that the domestic producers having a share of more than 50% of total Indian production have to necessarily participate for seeking levy of antidumping duty.

D.3 Examination by the Authority:

28. The issues raised by various interested parties with regard to standing of domestic industry are examined as under:
- Rule 2 (b) of the AD rules defines the domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"
 - The application has been filed M/s Steel Authority of India Limited, M/s Rashtriya Ispat Nigam Limited, M/s Usha Martin Limited and M/s JSW Steel Limited. The production of the aforesaid four producers accounts for a major proportion of the total domestic production. The application has also been supported by two domestic producers, namely, Tata Steel Limited and Jindal Steel and Power Limited.

- c. With regard to imports by M/s Usha Martin Limited, it is noted by the Authority that M/s. Usha Martin Limited has not imported the subject goods during POI as is evident from the certificate provided by M/s Usha Martin Limited along with the application filed with the Authority. The mentioning of name of M/s Usha Martin Limited by DI on page 93 of the application under the list of known importers is merely a clerical mistake as admitted by DI.
- d. With regard to the issue that Applicant producers constitute mere 40% of the total production in India and do not satisfy the requirement under Rule 2(b) the AD Rules, Authority notes that domestic industry means the domestic producers whose collective output constitutes a major proportion of the total domestic production. The phrase used is "major proportion" not "majority proportion". There is no express requirement that Applicants must constitute 50% or more of the total domestic production in order to have a major proportion. There are judgments mentioning that less than 50% of the total production would satisfy the requirement of major proportion under the Rules.
- e. Explanation to Rule 5 of AD Rules states that the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application. Authority notes that there is no opposition to the present application from any domestic producers of subject goods in India.
- f. The Authority further notes that the share of Petitioners along with supporters is 65% of the total Indian production of Wire Rods as shown in the table below:

Particulars in MT	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015-Dec 2015 ((A)	POI (July 2015-Dec 15)	POI (A)
Petitioners						
Rashtriya Ispat Nigam Limited	267,404	354,645	295,837	445,350	234,693	469,386
Steel Authority of India Limited	306,753	321,095	288,016	428,943	226,705	453,409
JSW Steel Ltd	593,907	617,646	602,931	596,314	284,906	569,812
Usha Martin Ltd	309,908	315,892	316,281	309,851	156,841	313,683
Petitioners' Total Production	1,477,972	1,609,278	1,503,065	1,780,457	903,145	1,806,291
Supporters' Total Production	1,006,800	1,037,081	1,034,350	1,102,147	556,268	1,112,536
Other Producers	1,090,931	1,571,109	1,461,720	1,603,483	781,026	1,562,052
Total Domestic Production	3,575,703	4,217,468	3,999,134	4,486,087	2,240,439	4,480,879
Share of Petitioners	41%	38%	38%	40%	40%	40%
Share of Petitioners & Supporters	69%	63%	63%	64%	65%	65%

Accordingly, the production of applicants constitutes major proportion of the total domestic production and therefore Authority does not find it relevant to consider the argument regarding imports made by the supporters.

29. Therefore, the Authority holds that the applicants command a major proportion of the total domestic production of the subject goods in India and for the purpose of this investigation the applicants satisfy the standing requirement in terms of Rule 5(3) and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

D. De Minimis Limits

30. As per the import data received by the Authority from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the data furnished by the cooperating exporters from the subject country, the imports of the subject goods from the subject country are found to be above the *de minimis* level.

E. Miscellaneous issues

31. Various interested parties have raised several issues with respect to the present investigation, including methodologies of dumping determination and injury claims of the domestic industry. While the issues regarding the dumping and injury determination have been dealt in the appropriate places, the general issues raised by the parties to the investigation have been examined hereunder. For the sake of brevity, the submissions of the parties and issues raised therein have been summarized as follows:

F.1. Miscellaneous issues raised by the interested parties

- a. The Authority did not issue notice to all the interested parties including the Association as soon as it was satisfied that there was sufficient evidence to justify initiation. This is in contravention of Article 12.1 of the ADA. The Authority failed to disclose the Application to the domestic producers in India for seeking opposition to the application as mandated under AD Rules.
- b. The subject goods are largely consumed captively by the producers. The Authority is requested to collect the data for the same from the petitioners.
- c. The PUC includes wide range of products which vary significantly in terms of price and cost. The DI has resorted to excessive confidentiality. The costing and price information provided by the DI hampers provision of any meaningful comments.
- d. Ball and Rolled Bearing Manufacturers Association have submitted that there is a wide difference between the quantum of imports reported by the applicants and the data sorted by the Association. It has been requested to submit the details of imports considered for determination of PUC. Applicants have relied on IBIS data which is not authenticated by DGCIS who is mandated official organization for collection, compilation and dissemination of India's Trade statistics and commercial information.
- e. Some interested parties have contended that the domestic industry has been afforded multiple protections in the form of increase in basic customs duty ("BCD") and imposition of a Minimum Import Price ("MIP").
- f. The POI and injury period is a deviation from all the past practices adopted by the Authority. The POI in the subject investigation is taken for a period of six months which is contrary to the WTO Anti-dumping Committee recommendation (G/ADP/6, adopted by the Committee on 5 May 2000). Authority is requested to consider extending the POI upto June 2016. The POI selected is inconsistent with the Trade Notice No. 2/2004. There is an absolute overlap between the POI and April 15 to December 15 period which is provided as one of the previous years for comparisons. Interested parties also contend that post POI trends should be examined.
- g. The ROCE of 22% for computing NIP is very high. Reliance is placed on the judgement of Hon'ble CESTAT in the case of Bridgestone Vs. Designated Authority.
- h. There is no history of dumping of subject goods as no such investigation has ever been initiated in India. Therefore, retrospective duty cannot be levied in the present investigation due to absence of any history of dumping.
- i. Some of the interested parties have brought into the notice that the correctness certificate provided in the petition by RINL is dated 25th May, 2016 and the investigation was initiated on 2nd June 2016 meaning thereby the investigation was initiated in merely 7 days from the submission of the petition. This clearly shows that the Authority proceeded in extreme haste.
- j. Initiation of investigation is bad in law due to misleading data furnished by the applicant and improper evaluation of data by the Authority.

F.2. Miscellaneous submissions made by the Domestic Industry and considered relevant by the Authority are as follows:

- a. Increase in basic customs duty is a policy decision taken by the Government of India. Increase in the BCD cannot be considered as a remedy for countering injurious dumping. Further, the MIP imposed on certain iron and steel products is no longer applicable as of 4 February 2017. Therefore, the subject goods in the instant investigation are not subject to the MIP.
- b. Some interested parties are of the view that 22% return on capital employed is not justified in calculating non-injurious price. The domestic industry strongly objects to the above contention and submits that none of the interested parties have adduced evidence to demonstrate why 22% return on capital employed is not justified. In fact, in two recent CESTAT rulings, it has been observed that 22% return on capital employed is valid as per the consistent practice of the Designated Authority and the onus is on the party refuting it to demonstrate with evidence why 22% return is not justified. In this regard, the Designated Authority's attention is invited to CESTAT rulings in Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority, Final Order No. AD/A/53541/2015-CU[DB] dated 27 November 2015 and

Eximcorp India Pvt. Ltd. v. Designated Authority, Final Order No. AD/A/53462/2016-CU[DB] dated 12 September 2016. In view of the above CESTAT orders, 22% return on capital employed is valid in the present case and should be affirmed definitively in the final findings.

- c. Section 9A (3) of the Act is with reference to history of dumping of the product. Petitioners request the Authority to recommend retrospective levy of anti-dumping duty on the subject goods because the conditions for retrospective levy of antidumping duty are fully satisfied.
- d. There is evidence of dumping of subject goods which is evident from the fact that many country including Australia, Canada, EU, USA etc. have initiated anti-dumping investigation against import of Wire Rods from China PR. Massive dumping of PUC into India has taken place in a relatively short period of time causing injury to the domestic industry.
- e. Exporters are well aware that they are resorting to dumping which is causing injury to the domestic industry since import prices of PUC have reduced significantly as evident from the landed values for subject country.

F.3 Examination by the Authority

32. Miscellaneous submissions made by the interested parties and considered relevant by the authority are examined and addressed as follows:

- f. As regards the submission that Authority has not issued notice to all the interested parties, it is the practice of the Authority to intimate only known parties at the time of initiation. Further, under Article 12.1, Authority is required to inform interested parties known to the investigating authorities. Further, any other interested party, which is not known to the Authority at the time of initiation, can submit its request and get non confidential version of application.
- g. With regard to the issue of captive consumption, Authority has already collected the same from the applicants.
- h. With regard to the issue that PUC covers wide range of products which vary in terms of price and cost, Authority notes that PUC is wire rods only and the variation in price and cost is only because of availability of PUC in various grades and sizes.
- i. The Authority notes that the production quantity figures for India have been sourced from the JPC data only wherever necessary. Further, Authority has relied upon DGCI&S import data in the present case.
- j. The interested parties have submitted that the Indian Domestic Industry is seeking over-protection, as it has been afforded multiple protections in the form of increase in basic customs duty ("BCD") and imposition of a Minimum Import Price ("MIP"). In this regard, the authority notes that:
 - i. Increase in basic customs duty is a policy decision taken by the Government of India. Increase in the BCD cannot be considered as a remedy for countering injurious dumping.
 - ii. MIP was introduced by Government of India as a temporary measure and the same was in force for the subject goods till 4th February 2017.
- k. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of a public file.
- l. With regard to the contention of the interested parties that period of investigation should be more than 6 months, the Authority notes that according to recommendation of committee on anti-dumping practices (WTO document no. G/ADP/6 dated 16 May 2000):

"...the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable"

- m. Therefore, in view of above recommendation, 6 months period can be taken as the POI. The Authority has taken six months POI in several other investigations as well. The Authority also notes that the initiation of the present investigation is in no way in violation of Trade Notice No. 2/2004.
- n. With regard to the contention of the interested parties that post POI trends should be examined, the Authority notes that in an original investigation, post POI trends are not relevant. In case of reviews initiated in terms of Rule 23 of the AD Rules, would post POI trends become relevant because the Authority has to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if anti-dumping duty is withdrawn.
- o. As regards the request for retrospective imposition of anti-dumping duty, Section 9A(3) of Customs Tariff Act provides as follows:

If the Central Government, in respect of the dumped article under inquiry, is of the opinion that

- i. there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping would cause injury; and
- ii. the injury is caused by massive dumping of an article imported in a relatively short time which in the light of the timing and the volume of imported article dumped and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied,

the Central Government may, by notification in the Official Gazette, levy anti-dumping duty retrospectively from a date prior to the date of imposition of anti-dumping duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under that sub-section, and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such duty shall be payable at such rate and from such date as may be specified in the notification.

- p. Taking into account the facts of the case, the Authority does not find it an appropriate case for recommendation of retrospective imposition of anti-dumping duty.
- q. The present investigation has been initiated on the basis of prima facie analysis of the information/data furnished by the applicants showing dumping of subject goods from the subject country, injury to the applicants on account of the said dumping and causal link between the two. With regard to the contention of the opposing interested parties that the initiation of investigation is bad in law due to misleading data furnished by the applicants and improper evaluation of data by the Authority, the Authority notes that it has prima facie satisfied itself about the accuracy and adequacy of information on the basis of information furnished by the petitioners at the time of initiation.

F. Normal Value, Export Price and Dumping Margin

NORMAL VALUE

33. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Provisions relating to Non- Market Economy country

34. Annexure-I to AD rules states as under:

7. In case of imports from non-market economy country, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a non-market economy country

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:

(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph”.

Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

35. Various submissions made by the interested parties with regard to MET, Normal value, export price and dumping margin and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- a. While determining the normal value for China PR, domestic selling prices and cost of Chinese producers should be considered as China PR has transitioned to a market economy in December 2016 as per its accession protocol to the WTO.
- b. Applicants have directly constructed normal value without considering the constructed value in China or the price from any other third country to India in violation of Annexure I(7) of the AD Rules. Reliance is placed on the decision of the Apex Court in the case of Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. V. Exide Industries Ltd & Others wherein it was held that Authority is required to construct normal value after sequentially applying the different methods mentioned in Annexure I(7) of the AD Rules.
- c. The petitioners have considered constructed normal value based on cost of the DI. The cost of most efficient producer should alone be considered based on consistent practice of the Authority.
- d. The Authority has violated Article 5.3 of the ADA by accepting the export price and normal value data for different periods. The Authority has not determined the dumping margins by making comparison between the export price and normal value in respect of sales made at same point of time. Applicants have not disclosed whether the normal value has been determined for POI period or any other period.
- e. Jiangsu Shangang International Trade Co. Ltd. ("Jiangsu") has requested the Authority to accept its questionnaire response and compute an individual dumping margin for its supply chain as there is no obligation on its related producers to provide data in Appendix-2 because they have not exported to India. Further, Jiangsu has submitted that the Authority has arbitrarily rejected the questionnaire responses filed on behalf of Jiangsu Shaganag International Trade Co. Ltd as unrelated traders have not furnished the information and has accordingly applied 'facts available'.
- f. Benxi Beitai Gaosu Steel Wire Rod Co. Ltd. ("BBG") has submitted that non-filing of response of M/s. Ningbo CIMEI Import & Export Co. Ltd. (Ningbo), its related exporter should not be considered as quantum of exports through Ningbo to India is insignificant in relation to its total exports to India. Further, Ningbo has filed its belated response on 04.11.2017. It has also been submitted that non reporting of sales in Appendix 2 by Benxi Beiyang Iron and Steel Group Imp. and Exp. Corp. Ltd., China (BBIE), related exporter of BBG, should not be considered as BBG has reported these details in Appendix 2 provided as part of response filed by it and BBIE is only acting as export agency for its producer BBG. In view of the above, BBG has requested the Authority to accept its questionnaire response and compute an individual dumping margin for its supply chain.
- g. Jiangyin Xingcheng Alloy Material Co. Ltd. ("JXAM"), producer and Jiangying Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd. ("JXSS"), exporter; have submitted that producer and exporter are related parties and the producer in fact referred to the Appendix 2 filed by the related exporter to avoid duplicate filing as the exporter is the custodian entity of relevant exports data to India. Notwithstanding the above, Appendix 2 was once again filed on behalf of the petitioner but a week prior to the PF. In the view of above, response filed by JXAM and JXSS should not be rejected for the reason that producer has not provided Appendix in the EQ response.
- h. Appendix 2, filed by interested parties after expiry of initial 40 days time to file EQ response, should be accepted by the Authority.

Submissions made by the Domestic industry

36. Various general submissions made by the domestic industry with regard to MET, Normal value, export price and dumping margin during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. The contention raised by interested parties that the Appellate Body in EC-Fastener provided strong justification for China to automatically obtain market-economy status is incorrect. There is no such observation in the Appellate Body Report. The Appellate Body Report was adopted by the WTO DSB on 28 July 2011 i.e. five years before the date of expiry of 11 December 2016. In EC-Fastener, imposition of definitive anti-dumping duties by the EU on imports of certain iron or steel fasteners originating in China PR was under challenge before the WTO DSB. Clearly, the issue regarding China's status as a market economy country was not before the WTO Appellate Body. Interested parties have also not cited any specific observations from the Appellate Body report to support their

contention that 'strong justification' was provided by the Appellate Body to grant market economy status to China PR automatically.

- b. China's accession protocol does not provide that China will get market-economy status after fifteen years automatically. It just says that a very specific provision of para 15 (a)(ii) will cease to apply. The other parts of Article 15 (including Article 15(a)(i)) continue to apply. Article 15(a) clearly provides that the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices. Article 15(a)(i) further provides that Chinese prices or costs shall be used if the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail. Given these explicit provisions in the Accession protocol, the interpretation advanced by the interested parties that China must be treated as market economy country after 15 years results in imputing meaning to a mere expiration provision and reading into the text something that is not there. It also negates all the other provisions of the protocol which are in force. Rules of international treaty interpretation simply does not allow such possibility, leave alone the rule of pacta sunt servanda that the interested parties rely on at length to substantiate its contention.
- c. Annexure 1, Rule 8(4) of the Anti-dumping Rules, 1995 clearly provides that the Designated Authority (DA) may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of criteria, has been treated as a market economy country for the purpose of anti-dumping investigations, by a WTO member country. There is no evidence provided by the interested parties to satisfy this criteria for China PR.
- d. The date of initiation of present investigation was June 2, 2016. The date of expiry contemplated in China PR's accession protocol is December 11, 2016. Even if the expiration of provision has the stated effect as alleged by the interested parties, the same cannot be applied with retrospective effect so as to apply to investigations that were initiated prior to December 11, 2016.
- e. None of the Chinese producers can satisfy market economy status. None of the WTO Member country has granted market economy status to Chinese producers on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria.
- f. Unless the responding Chinese exporters conform to the standards laid down under the Rules, the Designated Authority is required to determine the normal value in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules.
- g. None of the interested parties have suggested a surrogate country to the Designated Authority. Therefore, there is no merit in the submissions made by the interested parties that the Authority should have proceeded sequentially while determining the normal value for China PR.
- h. Petitioners urges the Authority to maintain the same stand taken in respect to the submissions filed by the Chinese exporters in the final findings as well. The incomplete responses filed by producers/exporters should not be accepted by the Authority and the dumping margin for these supply chains should be based on best facts available.
- i. With regard to cooperation by interested parties, the domestic industry further submits that there is a strict requirement placed by investigating authorities in other WTO member countries. In case of countervailing duty investigation concerning imports of Certain Corrosion Resistant Steel Products from India conducted by United States, the US Department of Commerce ("USDOC") has treated an exporter as non-cooperative just because the exporter has failed to inform the USDOC that related company supplying a miniscule quantity of raw material was in operation for the final two months of the POI.
- j. It is the global practice that suppression of facts and non-cooperation should lead to rejection of questionnaire response. The Designated Authority should make similar obligations on exporters and treat them non-cooperative for the reasons cited above.
- k. It is also requested that in calculation of the ex-factory export price, bank charges should also be reduced as deduction from the export price of the exporters for fair comparison wherever not deducted.

Examination by the Authority**Market Economy claims for Chinese producers**

37. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

38. Article 15 implies that provisions of one of the sub-paragraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this sub-paragraph expired on 11th Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is July 2015 to December 2015. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority is entitled to use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

39. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as

a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

40. As per Paragraph 8, Annexure I to the AD Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provides information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 . The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-
- a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values.
 - b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts.
 - c. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms.
 - d. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
41. It is noted that none of producers of subject goods in China PR have claimed market economy treatment. Accordingly, the Authority is not required to examine any of the above criteria and held that producers/exporters from China PR are not operating under market economy conditions.

Determination of Normal Value

42. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following parties have filed exporter questionnaire responses:
1. Jiangsu Shagang Material Trade Co. Ltd. (Exporter)
 2. B&L Metal (HK) Limited (Exporter)
 3. Jinagsu Runzhong High Tech Co. Ltd (Producer)
 4. Zhangjiagang Shajing Steel Co. Ltd. (Producer)
 5. Zhangjiagang Hongxing Gaoxian Co. Ltd (Producer)
 6. Zhangjiagang Rongsheng Steel Making Co. Ltd. (Producer)
 7. Jinagsu Shagang International Trade Co. Ltd. (Exporter)
 8. B&L International Investment Co. Ltd. (Exporter)
 9. Zhangjiagang Hongchang Gaoxian Co. Ltd.(Producer)
 10. Zhangjiagang Runzhong Steel Co. Ltd. (Producer)
 11. Xinsha International Pte. Ltd. (Exporter)
 12. Minmetals Yingkou Medium Plate Co. Ltd. (Producer)
 13. Sinomaterial International Co. Ltd. (Exporter)
 14. Manuchar Steel Hong Kong Limited Exporter)
 15. Burwill Resources Limited (Exporter)
 16. Jiangsu Yonggang Group Co. Ltd. (Producer)
 17. Genesis Resources Co. Ltd (Hong Kong)
 18. Smart Timing Steel Limited (Exporter)

19. Toptip Holding Pte. Ltd. (Exporter)
 20. Zenith Steel Group Co. Ltd. (Producer)
 21. Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co. Limited (Exporter)
 22. Unisteel International DMCC (Exporter)
 23. Win Faith Trading Limited (Exporter)
 24. Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited (Exporter)
 25. Benxi Beiyong Iron and Steel Group Imp. And Exp. Corp. Ltd. (Exporter)
 26. Benxi Beitai Gaosu steel Wire Rod Co. Ltd. (Producer)
 27. Future Materials Industry (Hong Kong) Co. Limited (Exporter)
 28. Jiangyin Xingcheng Alloy Material Co., Ltd (Producer)
 29. Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd (Exporter)
43. Further, the following exporters/traders have filed only Appendix-2 and 3A instead of filing the complete questionnaire response.
1. HongKong Grand International Co. Ltd.
 2. Hyosung Corporation
 3. Steelco Pacific Trading Limited
 4. Steelforce Far East Ltd.
 5. Tata International Metals (Asia) Limited
 6. Unisteel International DMCC (Seperately filed)
44. It is noted that none of the producers of subject goods in China PR have claimed market economy treatment. Therefore, the Authority has adopted the constructed normal value for determination of the normal value in terms of Para-7 to Annexure-1 to the Rules.
45. With regard to the contention of interested parties that Authority is required to construct normal value after sequentially applying the different methods mentioned in Annexure I(7) of the AD Rules, Authority notes that none of the interested parties have either suggested a surrogate country to the Designated Authority or provided any credible data in this regard. Therefore, the authority has constructed the normal value on the basis of best available facts as described in the following paragraphs.
46. With regard to contention that Authority has violated Article 5.3 of the ADA by accepting the export price and normal value data for different periods, the Authority notes that submission made by the interested parties is devoid of any merit as normal value and export price is determined for POI only.

Methodology for determination of normal value

47. In view of the above, the normal value for China PR is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. As per the provisions of Para 7 of Annexure I, the normal value in China PR is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country, or the constructed value in a market economy third country, or the export prices from such a third country to any other country, including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include reasonable profit margin.
48. In the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country, the Designated Authority has constructed the normal value for China PR on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the Normal Value for all the exporters from China PR has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

EXPORT PRICE

M/s Benxi Beitai Gaosu Steel Wire Rod Co., Ltd., China PR (Producer) through related traders M/s. Benxi Beiying Iron and Steel Group Imp. and Exp. Corp. Ltd, China PR, M/s. Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited (Hong Kong) and unrelated traders, M/s. Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co. Limited (Hong Kong), M/s. Win Faith Trading Limited (Hong Kong), M/s. Future Materials Industry (Hong Kong) Co. Limited (Hong Kong), M/s Ningbo CIMEI Import & Export Co. Ltd., China (Exporter / Trader) and M/s. Unisteel International DMCC (UAE)

49. From the response filed by M/s Benxi Beitai Gaosu Steel Wire Rod Co., Ltd., China PR ("BBG"), Authority notes that BBG is the producer of the subject goods in China PR. BBG sold the subject goods to its related company, M/s. Benxi Beiying Iron and Steel Group Imp. and Exp. Corp. Ltd. ("BBIE") who in turn sold the subject goods to another related trading company, M/s. Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited and also to unrelated traders, M/s. Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co. Limited (Hong Kong), M/s. Win Faith Trading Limited (Hong Kong), M/s. Future Materials Industry (Hong Kong) Co. Limited, M/s. Unisteel International DMCC (UAE), M/s. Ningbo CIMEI Import & Export and Manuchar Steel Hong Kong Limited. M/s. Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited and the above named unrelated traders exported the subject goods to India.
50. From the response submitted by BBG and BBIE, Authority notes that BBIE is a related trader of BBG and enters into contracts with customers and issues invoices in its own name. However, in the response filed by BBG it has been stated that BBIE is acting as an export agency of BBG. BBIE has not filed a complete response and has submitted only Appendix-9. BBG has however subsequently accepted these facts in its written submissions and has noted that it submitted Appendix-2 for BBIE on May 1, 2017 i.e. after issuance of the preliminary findings. Further, BBG has not shown name of customer as BBIE in its response. Accordingly, Authority is of the view that BBG and BBIE have tried to suppress and misrepresent the details before the authority.
51. Further, out of the above-mentioned companies, M/s Ningbo CIMEI Import & Export has filed its response on 4th November, 2016 i.e. after issuance of the preliminary findings and Manuchar Steel Hong Kong Limited has not reported any exports to India manufactured by BBG. Therefore, in view of absence of complete information from BBIE including suppression of facts by trader(s) and submission of responses after expiry of the deadline mandated for filing responses, the Authority does not accept the response filed by BBG and its traders/exporters. Accordingly, the export price for BBG is based on the facts available with the Authority.

Jinagsu Runzhong High Tech Co. Ltd, Zhangjiagang Shajing Steel Co. Ltd., Zhangjiagang Hongxing Gaoxian Co. Ltd, Zhangjiagang Rongsheng Steel Making Co. Ltd., Zhangjiagang Hongchang Gaoxian Co. Ltd., and Zhangjiagang Runzhong Steel Co. Ltd. (Producers) exported through related traders Jinagsu Shagang International Trade Co. Ltd., Jiangsu Shagang Material Trade Co. Ltd, Xinsha International Pte. Ltd. and unrelated traders B&L Metal (HK) Limited, B&L International Investment Co. Ltd., HongKong Grand International Co. Ltd., Hyosung Corporation, Steelco Pacific Trading Limited, Steelforce Far East Ltd, Tata International Metals (Asia) Limited and Unisteel International DMCC

52. From the response filed by above companies, Authority notes that subject goods were produced by six related companies namely, M/s. Jinagsu Runzhong High Tech Co. Ltd, Zhangjiagang Shajing Steel Co. Ltd., Zhangjiagang Hongxing Gaoxian Co. Ltd, Zhangjiagang Rongsheng Steel Making Co. Ltd., Zhangjiagang Hongchang Gaoxian Co. Ltd., and Zhangjiagang Runzhong Steel Co. Ltd.
53. The subject goods manufactured by these producers are exported through related traders namely, M/s. Jinagsu Shagang International Trade Co. Ltd., M/s. Jiangsu Shagang Material Trade Co. Ltd., M/s. Xinsha International Pte. Ltd. and unrelated traders namely, M/s. B&L Metal (HK) Limited (Hong Kong), B&L International Investment Co. Ltd., M/s. HongKong Grand International Co. Ltd., M/s. Hyosung Corporation, M/s. Steelco Pacific Trading Limited, M/s. Steelforce Far East Ltd, M/s. Tata International Metals (Asia) Limited, M/s. Unisteel International DMCC, Manuchar Steel Hong Kong Limited, M/s. Thyssenkrupp Mannex Asia Pte Ltd, UIL Hongkong Ltd., Gallop Resources Pte Ltd. M/s. Cumic Steel Limited and M/s. Smart Timing Steel Limited.
54. Out of the above mentioned companies, M/s. Thyssenkrupp Mannex Asia Pte Ltd, UIL Hongkong Ltd. Gallop Resources Pte Ltd. and Cumic Steel Limited have not filed any response. In addition, M/s. Smart

Timing Steel Limited and Manuchar Steel Hong Kong Limited have not reported exports to India manufactured by these producers. Further, the responses filed by M/s. HongKong Grand International Co. Ltd., M/s. Hyosung Corporation, M/s. Steelco Pacific Trading Limited, M/s. Steelforce Far East Ltd, M/s. Tata International Metals (Asia) Limited are grossly incomplete. These traders have submitted only Appendix-2 and 3A and no other information has been provided by these traders. Filing of EQR is not a mere formality to be fulfilled by submission of selective information as per the convenience of the exporters.

55. Further, none of the producers have submitted the information relating to exports to India in Appendix-2. In the absence of information in Appendix-2 from the producers it is not possible to ascertain the ex-factory export price to India.
56. In view of the aforesaid reasons, the Authority rejects the response by these companies. Accordingly, the export price for M/s. Jinagsu Runzhong High Tech Co. Ltd, Zhangjiagang Shajing Steel Co. Ltd., Zhangjiagang Hongxing Gaoxian Co. Ltd, Zhangjiagang Rongsheng Steel Making Co. Ltd., Zhangjiagang Hongchang Gaoxian Co. Ltd and Zhangjiagang Runzhong Steel Co. Ltd. is based on the facts available with the Authority.

Jiangsu Yonggang Group Co. Ltd. (Producer) exported through M/s. Sinomaterial International Co. Ltd., M/s. Manuchar Steel Hong Kong Limited, M/s. Burwill Resources Limited and other traders

57. From the response filed by the producers and exporters, Authority notes that subject goods were produced by Jiangsu Yonggang Group Co. Ltd and exported through unrelated traders namely, M/s. Sinomaterial International Co. Ltd., M/s. Manuchar Steel Hong Kong Limited, Burwill Resources Limited, Smart Timing Steel Limited, Metal One (Shanghai) Corporation, Navex Asia Limited, Wa Trading Co., Limited., Tewoo Metal (H.K.) Limited, Tata International Metals (Asia) Limited and Steelforce Far East Ltd.
58. Out of the above mentioned companies, Metal One (Shanghai) Corporation , Navex Asia Limited, Wa Trading Co., Limited., Tewoo Metal (H.K.) Limited, Tata International Metals (Asia) Limited, and Steelforce Far East Ltd have not filed response. Further, M/s. Smart Timing Steel Limited has not reported exports to India manufactured by Jiangsu Yonggang Group Co. Ltd. Further, quantity of exports to India reported by M/s. Burwill Resources Limited and Sinomaterial International Co. Ltd is not matching with the quantity reported by Jiangsu Yonggang Group Co. Ltd.
59. Therefore, in view of the aforesaid reasons including suppression of facts, the Authority rejects the response filed by these companies. Accordingly, the export price for Jiangsu Yonggang Group Co. Ltd is based on the facts available with the Authority.

Zenith Steel Group Co. Ltd. (Producer), Genesis Resources Co. Ltd (Hong Kong) Smart Timing Steel Limited (Hong Kong/Exporter), Toptip Holding Pte. Ltd. (Exporter)

60. From the response filed by the producer, M/s. Zenith Steel Group Co. Ltd, Authority notes that producer has exported the subject goods to India through Genesis Resources Co. Ltd (Hong Kong), Toptip Holding Pte. Ltd. (Singapore) and Win Faith Trading Limited, China PR. Win Faith Trading Limited, China PR has not cooperated with the Authority. Toptip Holding Pte. Ltd has further resold the entire quantity to another trader M/s. Cargill International Trading Co., Singapore who has not filed any response. Genesis Resources Co. Ltd (Hong Kong) has sold the subject goods to Smart Timing Steel Limited (Hong Kong) who in turn resold the subject goods to DHAMM SK A, Switzerland, which also failed to cooperate with the Authority.
61. Therefore, in view of non-cooperation by aforesaid traders/exporters, the Authority does not accept the response filed by these companies . Accordingly, the export price for Zenith Steel Group Co. Ltd is based on the facts available with the Authority.

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd. (Producer cum Exporter)

62. From the response filed by Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd. ("MYMP"), Authority notes that MYMP has exported the subject goods directly to India during the POI.

63. The sales to Indian customers are on CFR basis. MYMP has claimed adjustments on account of inland freight, port charges, ocean freight and bank charges and same have been allowed. The Authority has made further adjustment on account of non-refundable VAT. Accordingly, the weighted average export price has been determined for MYMP at ex-factory level and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Jiangyin Xingcheng Alloy Material Co., Ltd (Producer) exported through Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd

64. From the response filed by the producer and exporter, Authority notes that subject goods were produced by Jiangyin Xingcheng Alloy Material Co., Ltd ("JXAM") and exported through related trading company Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd ("JXSS"). At the time of issuance of Preliminary Findings, the Authority did not provisionally accept the response of JXAM on the ground that JXAM did not submit information relating to exports to India in Appendix-2 and in the absence of such information in Appendix-2 it was not possible to ascertain the ex-factory export price to India.
65. It has been subsequently submitted by JXAM that the company has submitted the Appendix-2 before the issuance of preliminary findings. The authority has examined this issue and found that JXAM had submitted Appendix-2 much after the due date. Despite belated submission, the authority has examined the response filed by JXAM & JXSS since JXAM in its initial submission had referred to Appendix 2 filed by the trader JXSS for its exports to India. The Authority on detailed scrutiny of the responses from JXAM and JXSS has however noted as under:
66. JXAM has submitted that its products have been exported to India and other 3rd countries through JXSS. Similarly, JXSS has submitted that it has exported the subject goods manufactured by JXAM to India and other 3rd countries. However, the exports quantity reported by JXAM in its response does not match with the exports quantity reported by JXSS in its response.
67. In Appendix-4, JXAM has reported that it has only exported the subject goods to 3rd countries and has not reported any exports to India in the said Appendix. So there is internal mismatch between the information provided by JXAM in its response.
68. JXSS has also not submitted information in Appendix-7 & 9. In the absence of the complete information in Appendix-7 & 9, it is not possible for the authority to ascertain whether JXSS has recovered its SGA expenses and made a reasonable profit on its exports to India.
69. Therefore, in view of above, the Authority does not accept the response filed by JXAM & JXSS. Accordingly, the export price for JXAM is proposed to be based on the facts available with the Authority.

Export Price for non-cooperating producers and exporters

70. The Authority notes that no other producer/exporter from China PR has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in China PR, the Authority has determined the weighted average export price for Wire Rods on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

DUMPING MARGIN

71. The export price to India (net of all the adjustments claimed by the exporter and accepted by the Authority) has been compared with the normal value to determine the dumping margin. The dumping margin during the POI for all the exporters/producers from the subject country has been determined as shown in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin Table

S.No	Country	Producer	Exporter	Normal Value USD	Net Export Price USD	Dumping Margin USD	Dumping Margin %	Dumping Margin Range %
1.	China PR	Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
2.	China PR	Others	Others	***	***	***	***	90-100

72. It is seen that the dumping margins are quite significant in respect of the exports made by all the producers-exporters of the product under consideration from the subject country.

G. Determination of Injury and Causal Link

73. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

74. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules.

Views of Exporter, importers and other Interested Parties regarding the injury claims of domestic industry

75. The submissions made by the opposing interested parties with regard to injury related issues and considered relevant by the authority are as follows:

- The injury, if any, to the DI is caused by factors including decline in export performance, increased interest costs, increased cost of sales per unit etc. Production capacity of the domestic producers has not increased in line with domestic demand. Demand of subject goods increased from 100 index units in 2012-13 to 160 points in POI (Annualised). The increase in imports is only to bridge the demand supply gap.
- JSW's Karnataka plant was closed during the POI (Q2) for which no disclosure has been made in the petition. Authority should provide revised injury information after making adjustments for the closure of Karnataka plant. The DI has expanded its capacity and the production of the DI has significantly improved from the base year. Thus there is no adverse impact on these factors.
- There is no adverse impact on profitability due to alleged imports. The profits of the DI have declined due to rise in per unit cost of interest from 100 points in 2012-13 to 177 point in the POI. Moreover, the negative price undercutting shows that the landed price of imports are not affecting the domestic prices.

Views of the domestic industry

76. The following are the submissions with regard to injury related issues made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:

- Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of PUC from the subject country have increased in absolute terms.

- b. Imports of the subject goods have increased relative to production and also relative to consumption in India as well in absolute terms.
- c. Market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand and the market share of imports from subject country sharply increased from 2012-13 to POI (A).
- d. The Domestic Industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.
- e. Inventories of the Domestic Industry have been on the rise as the Domestic Industry has not been able to increase its sales despite increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
- f. There is significant price depression and suppression due to low priced dumped imports coming into India.
- g. The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been drastically affected. The return on capital employed, net profits and cash profits have followed a negative trend during the entire injury period and the losses have further aggravated during the POI.
- h. The export performance of the Domestic Industry in no way has affected its financial and economic situation. Also, the petitioners have ignored the information related to exports while examining the injury parameters and the entire injury analysis is based only on domestic performance of petitioners.
- i. The analysis overwhelmingly indicates that the Domestic Industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India. There exists a strong nexus between the increase in dumped imports of the subject goods and the material injury being suffered by the Domestic Industry.
- j. At the time of placing orders with the domestic industry, the customers insist that the Domestic Industry must match the price with the offer given by the foreign producer during the same month, though the offer given by a foreign supplier would be delivered only after 2 months. Therefore, the proper comparison for price undercutting should be between the domestic sales realisation with two months lag. If the Authority takes into account this time lag issue, price undercutting would be evident.
- k. It is also pertinent to note that during the recent periods, the landed value of imports of the subject goods have declined much more than the decline in raw material prices. Further, it should be noted that imports have come at grossly low prices and the domestic industry has been forced to match such low prices to the extent that their prices have gone below the cost of production of the domestic industry.
- l. Interested parties have submitted that injury being suffered by the domestic industry is due to their own internal factors such as high fixed cost burden and underutilized capacities. These claims are very general and without any facts and figures to support. The fact that injury has been caused due to dumped imports of the subject goods in India has already been established. The domestic industry has been in existence since many years and has been doing well in the past.

Examination of the issues by the Authority

77. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under :
- a. The Authority notes that landed value of imports of the subject goods from the subject country has declined substantially during POI and the domestic industry had to lower its selling prices during POI to match the reduced landed value of imports .
 - b. With regard to the export performance of the domestic industry, the Authority notes that entire injury analysis is based only on the domestic performance of the petitioners.
 - c. The Authority has further analysed the contention of the interested parties to the effect that injury being suffered by the domestic industry is due to their own internal factors including high fixed cost burden and underutilized capacities. The fact that injury has been caused due to the dumped imports of the subject goods in India has been established in the succeeding paragraphs.

Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry**Assessment of Demand**

78. The demand of subject goods has been determined by adding the domestic sales of Indian producers of like product with the imports of the subject goods from all country. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The Authority notes that demand of subject goods increased over the injury period as can be seen in the table below:

Particulars (in MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015-Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Total dumped imports from subject country	1,60,582	1,16,366	7,70,493	8,27,721	4,95,732	9,91,463
Imports from other countries	2,03,688	71,595	1,00,927	1,06,142	53,835	1,07,670
Total imports	3,64,270	1,87,961	8,71,420	9,33,863	5,49,567	10,99,134
Domestic sales of petitioners	11,55,858	12,26,631	10,83,019	15,03,914	7,82,421	15,64,842
Domestic sales of supporters	6,21,818	6,22,535	6,63,185	7,07,817	3,63,094	7,26,188
Domestic sale of other producers	8,53,170	11,97,538	10,53,228	13,54,427	6,76,625	13,53,250
Total Demand/Apparent consumption	29,95,116	32,34,665	36,70,853	45,00,022	23,71,707	47,43,414

Import Volumes and Share of Subject country

79. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject country has been analyzed as under:

Particulars (in MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015-Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Dumped imports from subject country	1,60,582	1,16,366	7,70,493	8,27,721	4,95,732	9,91,463
Trend	100	72	480	515	309	617
Imports from other countries	2,03,688	71,595	1,00,927	1,06,142	53,835	1,07,670
Trend	100	35	50	52	26	53
Total Imports	3,64,270	1,87,961	8,71,420	9,33,863	5,49,567	10,99,134
Trend	100	52	239	256	151	302
Total Demand/Apparent consumption	2,995,116	3,234,665	3,670,853	4,500,022	2,371,707	4,743,414
Trend	100	108	123	150	79	158
Dumped imports from Subject Country relative to consumption	5%	4%	21%	18%	21%	21%
Production of Petitioners	1,477,972	1,609,278	1,503,065	1,780,457	903,145	1,806,291
Dumped imports from Subject Country relative to petitioners' total production	11%	7%	51%	46%	55%	55%

80. The Authority notes as under from the above table:

- Imports of subject goods from China PR have increased in absolute terms from 1,60,582 MT in 2012-13 to 9,91,463 MT in POI (A).

- b. Imports of subject goods from China PR have increased in relation to petitioners' production from 11% in 2012-13 to 55 % in POI (A).
- c. Imports of subject goods from China PR have increased in relation consumption in India from 5% in 2012-13 to 21% in POI (A).

Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

81. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

82. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression.

Price Undercutting

83. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. The domestic prices and margin of undercutting during POI is shown in the table below:

Particulars	Amount (INR / MT)
Landed Value	28,093
Domestic Selling Price	***
Price undercutting	***
Price undercutting as % of Landed Value	***
Price Undercutting Range %	(5)-5

84. The authority notes that the price undercutting is negative.

Price Suppression/Depression

85. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars (Rs. per MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015	POI (July 2015- Dec 15)
Cost to make and sell	***	***	***	***	***
Trend	100	98	101	91	87
Domestic Selling Price	***	***	***	***	***
Trend	100	96	98	75	72
Landed Value	***	***	***	***	***
Trend	100	98	89	75	73

86. It is noted that decline in the domestic selling price is higher than the decline in the cost of sales. The domestic selling prices of domestic industry have reduced to match the landed value of dumped imports from subject country. The imports were thus suppressing and depressing the prices of the domestic industry in the market.

Economic parameters of the domestic industry

87. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

88. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Installed Capacity (MT)	2,270,000	3,270,000	3,870,000	3,870,000	1,935,000	3,870,000
Production (PUC)	1,477,972	1,609,278	1,503,065	1,780,457	903,145	1,806,291
Production (Non-PUC)	1,192,670	1,173,342	1,305,434	1,330,699	675,003	1,350,007
Total Production	2,670,642	2,782,621	2,808,499	3,111,156	1,578,149	3,156,298
Capacity Utilization	118%	85%	73%	80%	82%	82%
Domestic Sales (PUC)	1,155,858	1,226,631	1,083,019	1,503,914	782,421	1,564,842

89. The Authority notes that multiple products can be manufactured using the same capacity. Accordingly, the capacity utilization has been calculated based on total capacity and total production.

90. Capacity utilization of the domestic industry has shown a decline. The domestic industry has been able to achieve a best capacity utilization of 118% during 2012-13. However, this has come down to 82% during the POI due to increase in dumped imports from the subject country.

Profits, return on investment and cash profits

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Profit before Tax (Rs. In crores) i.e PBT	***	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend	100	63	44	(211)	(112)	(224)
PBT (Rs./MT)	***	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend	100	59	47	(162)	(165)	(165)
Cash Profits (PBT+Depreciation) (Rs. crores)	***	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend	100	73	57	(148)	(79)	(158)
Cash Profit (Rs./MT)	***	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend	100	69	61	(114)	(117)	(117)
ROCE %	***	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend	100	73	79	(54)	(60)	(60)

91. The Authority notes the following from the above table:

- The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been substantially affected due to dumping of subject goods from subject country. It can be seen from the above table that domestic industry was earning decent returns till 2014-15.
- However, due to dumping from subject country during POI, domestic industry has not been able to recover its cost of sales leave aside earning a reasonable return on capital employed.

Market Share

92. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Demand (MT)	2,995,116	3,234,665	3,670,853	4,500,022	2,371,707	4,743,414
Indexed	100	108	123	150	79	158
Market Share						
Share of Petitioners	39%	38%	30%	33%	33%	33%
Share of Supporters	21%	19%	18%	16%	15%	15%
Share of Other Producers	28%	37%	29%	30%	29%	29%
Share of Subject country	5%	4%	21%	18%	21%	21%
Share of Other countries	7%	2%	3%	2%	2%	2%

93. From above table, the Authority observes that market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. Further, the Authority notes that market share of the imports from the subject country has increased over the injury period. This is due to the reason that imports from the subject country have captured the increase in demand.

94. The domestic industry has not been able to increase the sales of the PUC commensurate with the increase in demand because of the significant volume of dumped imports coming from the subject country.

Inventory

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Jul 2015- Dec 15)
Average Inventory (MT)	63,650	62,871	77,271	118,979
Trend (Indexed)	100	99	121	187

95. The Authority notes that the Domestic Industry is facing significant accumulated inventories. The levels of inventories have been increasing as compared to the base year. Due to increasing imports, the market share of the Domestic Industry has come down and the increased demand has been captured by imports.

Productivity of the domestic industry

96. The Authority notes that deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry. It can be seen in the table given below that productivity per employee has increased from 100 indexed points in 2012-13 to 114 indexed points during the POI.

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Productivity	***	***	***	***
Trend	100	103	100	114

Growth

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	POI(A)
Cost of Production	%	-2%	3%	-14%
Selling Price	%	-4%	2%	-27%
Profit/ Loss per unit	%	-41%	-20%	-448%
Return on Capital Employed	%	-27%	9%	-176%

97. The Authority notes that growth of the domestic industry with regard to capacity utilization, profits, return on investment, cash profits has been negative.

Ability to raise capital investments

98. The Authority notes that given the rising demand of the product in the country, the domestic industry has made significant investments in plant and machinery. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and further investment may get adversely affected.

Level of dumping & dumping margin

99. It is noted that the imports from the subject country are entering the Indian market at dumped prices and that the margins of dumping are significant.

Causal Link

100. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry has been done as follows:

Imports from third country

101. The imports from countries other than subject country are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry.

Contraction in demand

102. The demand for the subject goods has shown an increasing trend. Accordingly, fall in demand cannot be the reason for injury to the domestic industry. In fact, the domestic industry has not been able to increase its sale and market share commensurate to increase in demand.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

103. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

Developments in technology

104. The technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic injury.

Changes in pattern of consumption

105. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

Export performance

106. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. In fact, exports by the domestic industry have not materially declined. In any case, the authority has considered domestic performance wherever possible.

Performance of the domestic industry with respect to other products

107. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

Factors establishing causal link

108. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from the subject country. Causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
- Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the entire period of investigation.
 - Imports of the subject goods have increased relative to production and consumption in India.
 - Market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.
 - The Domestic Industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.
 - Inventories of the Domestic Industry have been on the rise, as the Domestic Industry has not been able to increase its sales despite increase in demand.
 - There is price suppression and depression due to low priced dumped imports coming in to India.
 - The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been drastically affected. This is evident from the fact that the domestic industry was earning decent profits and return on capital employed till 2014-15. However, during the POI, the profits and returns have turned into losses.

Conclusion on Injury and Causation

109. From the above examination of injury and causal link, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumping of the subject goods from the subject country. There has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject country in absolute terms throughout the injury period and in relation to production and consumption in India. The dumped imports have had significant adverse effect on the prices of the domestic industry in the market. The dumping margin for the subject country has been determined and is considered significant. Dumped imports from the subject country have adversely impacted capacity utilization of the domestic industry. Market share of the subject imports has significantly increased. Performance of the domestic industry has

significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on investments. The Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports from the subject country.

110. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry and compared with the landed values of the subject imports of the responding exporters to determine the injury margin. The landed value to India in respect of other producers and exporters in the subject country has been determined on the basis of the best available information. The injury margins have been determined as follows:

Injury Margin

S.No	Country	Producer	Exporter	NIP USD	Landed Value USD	Injury Margin USD	Injury Margin %	Injury Margin Range %
1.	China PR	Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	***	***	***	***	35-45
2.	China PR	All Others	All Others	***	***	***	***	50-60

111. The level of dumping margins and injury margins as determined are significant.

H. Post Disclosure Statement submissions by the Interested Parties

112. The post disclosure submissions have been received from various interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

Submissions made by the Domestic Industry

113. The submissions made by the domestic industry have been summarized as below:

- a. It has been submitted by the domestic industry that the reference price based duty has not been able to put adequate checks on the quantum of imports of the subject goods into India. The imports from the subject country have been significant even after imposition of provisional anti-dumping duty. In addition, it has also been noticed that the import prices have been hovering around the reference price fixed by the authority in the provisional findings despite there being a significant increase in the input costs after the POI. The domestic industry has requested the authority to recommend fixed duty in the final findings to give appropriate protection to the domestic industry. Application of fixed form of duty will ensure the effectiveness of measures as it would reduce the likelihood of price manipulation or circumvention.
- b. Recent trade remedial measures on wire rods from China by United States, European Union and Australia on non-cooperative exporters from China PR resulted in imposition of punitive rates of anti-dumping duty. Indian should also adopt similar approach in imposition of duty.

Submissions made by other interested parties

114. The submissions made by the other interested parties have been summarized as below:

- a. The difference in supplies from JXAM to JXSS is due to the stock maintained by JXSS. It is not a case that the material is directly dispatched from JXAM. JXSS maintains its stock and hence the difference.
- b. JXAM and JXSS have not claimed Market Economy Treatment and hence, did not provide the Appendix-7 & 9. There is a typographical error in Appendix-4 of JXAM. All sales shown under exports are sales to JXSS for sales in export market including India though it is mentioned as “exports to other countries”.
- c. BBG and BBIE have not suppressed any details from the Authority. There is an agency agreement between BBG and BBIE which allows BBIE for raising invoices and entering into contracts with

buyers on behalf of BBG and the proceeds received by BBIE shall after deduction of expenses be transferred to BBG.

- d. M/s Ningbo CIMEI Import & Export Co. Ltd. has already submitted their response. Therefore, the observation in the disclosure statement that we did not provide complete information on record is not borne out of the facts of the case.
- e. With regard to non-reporting of the exports to India by Manuchar Steel Hong Kong Limited, it is submitted that BBG have provided all the details as available with it and cannot be held liable for the information submitted by others as it has no control over them. We would also like to draw the kind attention of the Authority to the WTO Appellate Body Report in US-Anti-dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan (WT/DS184/ABR) dated 24th July 2001 wherein it was held that the investigating authorities cannot insist upon the absolute standards or impose unreasonable burdens upon the exporters with respect to the information which is not under their control.
- f. NEIL has again reiterated that SAIL had failed to deliver a particular order of SAE52100 grade and has requested for exclusion of SAE52100 & SAE 8720 from the scope of PUC. Further, NEIL has requested for PCN wise determination of dumping & injury margin.

Examination by the Authority

115. The Authority notes that most of the submissions by parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above ipso facto deal with these arguments of the parties. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere:

- a. With regard to the submission made by JXAM and JXSS, that difference in quantity is due to JXSS maintaining stock, the authority notes that no documentary evidence have been placed on record by the producer/exporter in this regard. Further, it is to be noted that Appendix-7 & 9 is required to be submitted by the trader/exporter irrespective of the fact whether MET has been claimed or not. The purpose of Appendix 7 & 9 is to examine whether the trader/exporter has recovered its SGA expenses and made a reasonable profit margin or not. Therefore, it is not possible to grant individual treatment to JXAM & JXSS.
- b. BBG and BBIE have not placed any new facts before the authority and have been unable to clarify the issue that if BBIE is not acting as an exporter, then how BBIE enters into contracts with customers in India and issues invoices in its own name. Further, M/s Ningbo CIMEI Import & Export Co. Ltd has submitted very delayed response, much after the issuance of preliminary findings. Further, some of the traders have suppressed the information. Therefore, authority is unable to grant individual treatment to BBG & BBIE.
- c. As regards the domestic industry's concerns regarding non-injurious price, the Authority observes that non-injurious price has been calculated in accordance with Annexure III of the AD Rules.
- d. With regard to the request of domestic industry to recommend anti-dumping duty in the form of fixed duty rather than reference price, authority notes that reference price based form of duty is appropriate for subject goods keeping in mind the facts and circumstances of the case and there are no compelling reasons to deviate from the form of antidumping duty recommended in the preliminary findings.
- e. With regard to the request made by NEIL for exclusion of SAE52100 & SAE 8720 from the scope of PUC, the authority notes that DI is manufacturing grades equivalent to SAE 52100 and SAE8720 and therefore this request of NEIL cannot be accepted.

I. Indian industry's interest & other issues

116. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

117. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these product. The domestic industry submitted that imposition of proposed duty shall have insignificant cost implications for the consumer. Therefore, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

J. Recommendations

118. After examining the submissions made and issues raised, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

- a) The product under consideration has been exported to India from the subject country below normal value.
- b) The domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the subject country
- c) The injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country.

119. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Anti-Dumping Rules and having established a positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.

120. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col 8 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 8. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975. The validity of the recommended definitive anti-dumping duty, if accepted by the Central Government, will be upto a period of five years from the date of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No. 51/2016-Customs (ADD) dated 2.11.2016.

DUTY TABLE

Sl. No.	Heading/ Sub heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7213 and 7227	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel or alloy steel, excluding (i) bars and rods containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process falling under	China PR	China PR	Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	535	MT	US\$

Sl. No.	Heading/ Sub heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
		tariff item 72131090 (commonly known as rebars or TMT bars), (ii) bars and rods of stainless steel falling under tariff heading 7221 and (iii) bars and rods of high speed steel falling under tariff heading 72271000.							
2.	- do -	- do -	China PR	China PR	Any combination other than at S. No.1		546	MT	US\$
3.	- do -	- do -	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	546	MT	US\$
4.	- do -	- do -	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	546	MT	US\$

121. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

Dr.INDER JIT SINGH, Designated Authority.